साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 24 12 - 18 जून 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

युद्ध के हासिल और सवाल पृष्ठ-6

राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ता रुझान चिंताजनक पृष्ठ-7

लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष का मज़बूत होना ज़रूरी

क्या कांग्रेस कसौटी पर खरी उतर पाएगी?

जब भी देश में विपक्ष कमज़ोर हुआ है सत्ताधारी पार्टी बेलगाम हो गई है, आज की भाजपा सरकार इसका जीवित उदाहरण है।

उदयपुर में जिस दिन कांग्रेस का तीन दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर समाप्त हुआ था, उसी दिन अहमदाबाद में भाजपा का दो दिवसीय चिंतन शिविर प्रारंभ हुआ था। इन दोनों चिंतन शिविरों को लेकर चर्चाएं स्वाभाविक हैं। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि विपक्ष मज़बूत हो लेकिन एक ओर भाजपा में चौबीस घंटे, सातों दिन बिना थके सक्रिय रहने वाले नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के साथ समर्पित टीम है जो हर पल रणनीति पर काम करती रहती है तो दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति क्या है? सबके बन में सवाल है कि उदयपुर में कांग्रेस के तीन दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर से संदेश क्या निकला है?

देशभर में फैले कार्यकर्ताओं के बीच क्या ऊर्जा का संचार हुआ है? आने वाले विधानसभा चुनावों में या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? आख़िर कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष कब मिलेगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर की उम्मीद में हवा में तैर रहे हैं।

चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस का नारा है -'भारत जोड़ो।' जब यह नारा सामने आया तो अपनी पूरी आयु पार्टी को समर्पित कर देने वाले एक बहुत पुराने कांग्रेसी ने मुझसे कहा कि पहले अपने घर को तो जोड़ो। भारत खुद-ब-खुद जुड़ जाएगा। आपकी पार्टी तो जुड़ी हुई है नहीं, देश की बात करने का मतलब क्या है? जी-23 के नेता जब पार्टी को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो उन्हें विद्रोही मान लिया जाता है। मतलब की बात तो यह है लोग की मज़बूती के लिए मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है और ये भूमिका निभाने का नैतिक दायित्व कांग्रेस का है, वह देश की सबसे पुरानी और लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाली पार्टी रही है।

चिंतन शिविर में असली चर्चा तो इसी बात पर होनी चाहिए थी कि जनता के मिजाज़ को कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है। मतदाता उस पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या चूक हो गई कि पार्टी आम जनता से कट गई। जनता से कट जाने की बात राहुल गांधी खुद भी कह रहे हैं। चिंतिन शिविर में इस बात को लेकर खास चिंता/चिंतन होनी चाहिए था कि लेकिन ऐसा कोई रोड मैप सामने नहीं आया कि जनता से कैसे जुड़ेंगे? जन भावनाओं को कैसे समझेंगे और अपनी बात कैसे समझाएंगे? उदयपुर के शिविर में भाग लेने के लिए राहुल गांधी यदि ट्रेन से पहुंचे तो उद्देश्य स्पष्ट था कि वे लोगों से कनेटक्ट करना चाहते थे। सुबह पांच बजे तक हर स्टेशन पर उनका स्वागत हो रहा था और वे कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे थे। यह अच्छी बात रही लेकिन उदयपुर की स्थानीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं के इस प्रश्न का क्या उत्तर है कि आलाकमान ने उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? ज़रा सोचिए कि उदयपुर के कांग्रेसियों को कितनी निराशा हुई होगी? ऐसी निराशा ही उत्साह ख़त्म करती है। एक प्रश्न यह भी हे कि इतने बड़े चिंतन शिविर में कांग्रेस ने अपने मंत्रियों और सांसदों को क्यों नहीं बुलाया? केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और महाराष्ट्र में वह सत्ता में भागीदार हैं। उसके पास केवल 53 सांसद हैं, फिर भी सबको नहीं बुलाया गया? राजस्थान के मंत्रियों को भी नहीं बुलाया गया।

शिविर के लिए 450 नेताओं को बुलाया था जिसमें 430 शामिल हुए। उनमें आधे से अधिक युवा थे जो राहुल गांधी के समर्थक हैं। शेष वो लोग थे जो कांग्रेस में विभिन्न पदों पर लंबे समय से विराजमान हैं। उनसे यह पूछ लीजिए कि हाल के सालों में उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। इनमें बहुत से वो लोग थे जो पार्टी को मजबूत करने के बजाय एक दूसरे को निपटाने में अपनी ऊर्जा ख़र्च करते हैं।

एक युवा कांग्रेसी ने मुझसे पूछा कि शीर्ष पदों पर विराजमान नेताओं में से कितनों का जनाधार है? कितने अपने बलबूते कोई चुनाव जीत सकते हैं? ये प्रश्न वाजिब है। ऐसी काली भेड़ों को जब तक पार्टी राजनीतिक वनवास नहीं देती तब तक पार्टी का मज़बूत होना एक सपना ही रहेगा। कांग्रेस ने भारत जोड़ों अभियान 2 अक्तूबर से कन्याकुमारी से शुरू करने का निर्णय लिया है कांग्रेस पर बारीक नज़र रखने वाले एक विशेषज्ञ ने मुझसे पूछा कि अमूमन यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर जाती है लेकिन कांग्रेस की यात्रा कश्मीर से क्यों नहीं शुरू हो रही है? लगे हाथ उन्होंने जवाब भी खुद ही दे दिया कि यदि यात्रा कश्मीर से शुरू करते तो सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद को साथ लेना पड़ता।

आज़ाद साहब पार्टी को ठीक करने के लिए कई बार आज़ाद खयाली व्यक्त कर चुके हैं इसलिए उन्हें कैसे साथ लेंगे? वे जी-23 में शामिल रहे हैं। उन्हें साथ लेने का मतलब होता आलोचकों के सामने झुकना। यह सब सुनते हुए 15वीं शताब्दी के महान व्यक्तित्व संत कबीर का दोहा याद आ गया। निंदक नियरे राखिए। निंदक यदि पास होगा तो अपनी कमज़ोरियां आपको पता चलेंगी, आप सुधार कर पाएंगे, बेहतर रास्ते पर चल पाएंगे। चापलूसों की फौज तो सल्तनत डूबाने का काम करती हैं कांग्रेस के जिन लोगों ने पार्टी को बेहतर बनाने के लिए कड़वी बातें की हैं, वे पार्टी के दुश्मन नहीं है। वे भाजपा के एजेंड नहीं हैं। उनकी बातें भी सुनी जानी चाहिए। पार्टी को यह सोचना होगा कि युवा नेता पार्टी से दूर क्यों जा रहे हैं? हार्दिक पटेल को पार्टी उम्मीदों के साथ लेकर आई थी, वे भाजपा की शरण में जा चुके हैं। उन्होंने बड़ी कड़वी बात भी कहीं है कि उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे नए दूल्हे की नसबंदी कर दी गई हो। सुनील जाखड़ क्यों पार्टी छोड़कर चले गए? जाखड़ ने बातें कड़वी की लेकिन वह चिंतन शिविर का विषय होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी अपने आंगन में सभी दलों के नेताओं का स्वागत कर रही है और कांग्रेस को कोई फिक्र ही नहीं है, यह बात बहुत कड़वी है लेकिन है सोलह आने सच कि पार्टी के पास इस समय कोई रोड मैप नहीं है। करीब तीन वर्ष से सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष पद संभाल रही हैं निश्चय ही वे भरपूर कोशिश कर रही हैं लेकिन इस बात से कौन इंकार करेगा कि बिना स्थायी अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं में भरोसा कैसे पैदा होगा.?

राहुल गांधी कहते हैं कि अध्यक्ष वे बनेंगे नहीं और उनके पास का कॉकस उन्हें ही अध्यक्ष की कुर्सी पर देखना चाहता है ताकि वे पॉवर सेंटर बने रहें। कांग्रेस के ही लोग मानते हैं कि राहुल गांधी की अनिश्चितता से पार्टी भी अनिश्चय की हालत में नज़र आती है। वैसे भी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की अपनी नीतियों को लेकर भी कन्फ्यज नज़र आ रही है। अब तो जो भाजपा कर रही है, कांग्रेस के नेता भी वहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि आलाकमान की पकड़ और मान क्या नीचे के स्तर तक क़ायम है? दरअसल जब ऊपरी स्तर पर निर्णय में देरी होती है, कन्फ्यूजन पैदा होता है तो कार्यकर्ताओं का हौंसला टूटता है। नई ऊर्जा पैदा नहीं होती है। कांग्रेस ने खुद को संभालने में बहुत देर कर दी है लेकिन उसे चाहने वाले अभी भी गांव-गांव में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। विश्वास की यात्रा वहां तक पहुंचे तो सही, सही निर्णय और कैडर में विश्वास भी आलाकमान को ही भरना है, तभी पार्टी का भविष्य अंधकार से बाहर आ सकता है, जिसके लिए तीनों गांधी को एक पैटर्न पर काम करने की ज़रूरत है, और हां वरिष्ठ नेताओं को भी हर हाल में साथ रखना है, चाहे वह कितनी भी आलोचना ही क्यों न करे, क्योंकि उनकी आलोचना ही कांग्रेस का उद्धारक साबित होगा।

पाक का विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से घटा

निरंतर आर्थिक संकट में फंसते जा रहे पाकिस्तान की मदद से उसके दोस्तों ने भी पल्ला झाड़ लिया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से उसके आर्थिक मदद मांगी थी लेकिन फिलहाल तीनों देशों ने उसे टरका दिया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से घटता जा रहा है। विदेशी कर्ज़ के बोझ से दबी अर्थव्यवस्था व भारी महंगाई के कारण उसका पहले से बुरा हाल है। कर्ज़ देने में चीन, यूएई व सऊदी अरब की आनाकानी की बात खुद पाकिस्तान के वित्तमंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने की है। इस्माईल के अनुसार पाकिस्तान को कर्ज़ देने में उसे मित्र देश भी सतर्कता बरत रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में इस्माईल के हवाले से कहा गया है कि वह मदद की गुहार लेकर सऊदी अरब और यूएई तो खुद गए थे, कुछ अन्य देशों से भी चर्चा की, लेकिन वे मदद को तैयार नहीं हैं। इन सभी देशों ने उन्हें सलाह दी कि पहले वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से मदद लें। इसके बाद ही वे पाकिस्तान की मदद पर विचार करेंगे। चीन के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान को कर्ज़ देने से इनकार कर दिया है। यदि वैश्विक वित्तीय संस्थाएं पाकिस्तान को कर्ज़ देंगी तो ही वह भी मदद करेगा। श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का भी बुरा हाल है। पाक विदेश मुद्रा भंडार भी तेज़ी से नीचे जा रहा है। यह एक साल से कम समय में आधा हो गया है। पाकिस्तानी रूपये में भी बड़ी गिरावट आई है। एशियाई देशों में श्रीलंका के रुपये के बाद पाकिस्तानी रुपया सबसे ज़्यादा नीचे आया है। पाकिस्तान के पास चीन, सऊदी अरब व अन्य देशों से पहले लिए कर्ज़ को चुकाने के भी पैसे नहीं हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चुतावनी दी थी कि जून 2022 के अंत से पहले पाकिस्तान पर करीब 5 अरब डॉलर का कर्ज़ हो जाएगा। देश इतना कर्ज़ नहीं चुका पाएगा। पाकिस्तान को अगर वैश्विक संस्थाओं से कर्ज़ नहीं मिला पाएगा तो वह डिफाल्टर हो जाएगा। पाकिस्तान में ज़बरदस्त महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इसी कारण हाल में पीएम शाहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि यदि ख़ैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्र महमूद खान 24 घंटे में आटे के दाम नीचे नहीं लासके तोवह अपने कपड़े बेचकर लोगों को सस्ता आटा मुहैया कराएंगे। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक लीटर पेट्रोल के लिए 179.86 रुपये, एक लीटर डीजल के लिए 174.15 पाकिस्तानी रूपये चुकाना पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में एक लीटर दूध की कीमत 144 पाकिस्तानी रूपये हो गई है। इसी तरह यहां एक पैकेट ब्रेड 94 रूपये से मिल रहा है। एक किलोग्राम चावल खरीदने के लिए लोगों को 180 से 200 रुपये तक देने पड़ रहे हैं। एक अंडा 16 रूप से और एक किलोग्राम पीनर 904 रुपये का मिल रहा है।❑❑

उइगर मुस्लिमों के दमन में चीन का शीर्ष नेतृत्व शामिल

चीन ने उत्तर पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकारों के हनन व उन पर अत्याचारों में देश का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से लिप्त है। चीन की पुलिस और बंदी शिविरों से लीक हुए हज़ारों दस्तावेज़ों से इसकी पुष्टि हुई है। इनसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के शीर्ष नेतृत्व व राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भूमिका पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। शिनजियांग के बदनाम बंदी शिविरों में उइगर मुस्लिमों को व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण के नाम पर रखा जाता है। 2018-19 में यह सिलसिला चरम पर था। 2020 तक 20 लाख लोगों को इन शिविरों में रखा गया। उधर, चीन की सरकार का दावा है कि इन शिविरों में बंदियों के दिल दिमाग़ को साफ कर उन्हें काम में लगाया जाता है। लीग दस्तावेज़ों के आधार पर आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2017 के बाद से इन शिविरों में बड़ी संख्या में उइगरों प्रशिक्षुओं को दंडित किया जाता है। कई को बिना किसी कारण के हिरासत में लिया जाता है। इन्हें चीन के प्रति अविश्वसनीय माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शिनजियांग पुलिस की लीक फाइल्स में उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचार की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। शिनजियांग में चीन ने उइगर मुस्लिमों को बंदी रखने के लिए कई शिविर बनाए गए हैं। हालांकि, चीन इन शिविरों को शिक्षा या पुनर्वास केन्द्र बताता है। चीन में उइगर मुसलमानों को आपसी झगड़े जैसे मामूली या झूठे आरोप तक में 5 से 25 वर्ष तक की क़ैद की जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जांच राज्य में वर्ष 2014 के बाद से लंबी सज़ा के लिए उन पर आतंक फैलाने, अलगाववाद और नफ़रत फैलाने के अरोप लगाने के मामले तेज़ी से बढ़े हैं।

ग़ैर नौकरशाह उपराज्यपाल होने के मायने

केन्द्र की भाजपा की अगुआई वाली राजग की सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवाआईसी) के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना को इसी 23 मई को दिल्ली का 21वां उपराज्यपाल नियुक्त किया। उन्होंने 26 मई, 2022 को कामकाज संभाल लिया। वे दिल्ली के पहले मौजूदा केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर समेत कई केन्द्र शासित प्रदेशों में ग़ैर नौकरशाह नियुक्त करने का सफल प्रयोग किया है।

दिल्ली में उपराज्यपाल ही असली शासक है, इसे केन्द्र सरकार ने बार-बार विभिन्न आदेशों से साबित किया है। ग़ैर आरक्षित विषयों पर उपराज्यपाल की भूमिका केवल सलाह की होने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले वर्ष संविधान संशोधन करके उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाए गए। पिछले दिनों संविधान संशोधन करके तीन नगर निगमों को एक किया गया और निगमों पर पूरा नियंत्रण केन्द्र सरकार का कर दिया गया। 15 जून को दिल्ली के राजेन्द्र नगर विधानसभा के उपचुनाव होने है। फिर नए परिसीमन के बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे। उसमें उपराज्यपाल के घर-दफ्तर (राजनिवास) की कोई सीधी भूमिका न होने के बावजूद इस बदलाव का असर कहीं न कहीं दिख सकता है।

विनय कुमार सक्सेना केवीआइसी के अध्यक्ष के अलावा केन्द्र सरकार की अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे हैं। आमतौर पर उपराज्यपाल का कार्यकाल पांच साल का होता है लेकिन वास्तव में यह केन्द्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह कब तक बदलाव नहीं करती है।

आज़ादी के बाद 20 वर्ष तक दिल्ली में मुख्य आयुक्त ही दिल्ली का शासक होता था। 1966 में मुख्य आयुक्त रहे आदित्य नाथ झा पहले उपराज्यपाल बने। तब से अब तक 21 बार उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई। उनमें जगमोहन और तेजेन्द्र खन्ना दो-दो बार उपराज्यपाल बनाए गए। अब एक उपराज्यपाल में चार आइसीएस, 12 आइएएस, दो आइपीएस एक आइएसएफ और दो पूर्व रक्षा अधिकारी रहे हैं। केन्द्र में किसी भी दल की सरकार रही है, उसने उपराज्यपाल के पद को ताक़तवर ही बनाया है। चार जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ यह फैसला दे चुकी है कि दिल्ली में ग़ैर आरक्षित विषयों में दिल्ली सरकार फैसला लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हे, लेकिन यह कह कर कि दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश ही रहेगा, राज्य नहीं बन सकता है, उसकी हद तय कर दी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को दरकिनार करना शुरू कर दिया।

दिल्ली को पूर्ण राज्य का आंदोलन चलाने वाली भाजपा की केन्द्र में 1998 से 2004 तक सरकार रही। उस दौरान और दोबरा 2014 से भाजपा की सरकार रहने के दौरान भाजपा नेता इस पर चुप्पी लगाए रहे। कांग्रेस के दबाव में और 2003 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता को जवाब देने के लिए तब के गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने 18 अगस्त, 2003 को दिल्ली राज्य विधेयक (2003 विधेयक संख्या 68) को प्रस्तुत कर दिया। उसमें भी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को प्रस्तावित शासन से अलग किया गया था और पुलिस व लोक प्रशासन को उपराज्यपाल के माध्यम से काम करवाने की व्यवस्था की। उसे मंत्रालय की स्थायी समिति में विस्तार से अध्ययन को भेजा गया। उस समिति की दो ही बैठक हो पाई और लोकसभा भंग हो गई तब से इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है।❑❑

गुजरात से दो जून की रोटी की तलाश में आए रघु दिल्ली में गंवा बैठे किडनी

किडनी के धंधेबाज़ों ने पैसे के लिए इंसानियत तक को ताख पर रख दिया और उस व्यक्ति को तलाश कर रहे थे, जिसे पैसों की ज़रूरत थी। ज़िन्दगी के थपेड़ों से टूटकर गुजरात से दिल्ली पहुंचे रघु भी इनके चंगुल में इस तरह फंसे कि 24 वर्ष की आयु में ही एक किडनी गंवा बैठे। रघु की आप बीती सुन पुलिसवालों की आंखें भी नम हो गईं। अब रघु को इस बात की चिंता सता रही है कि एक किडनी के सहारे उसकी बाकी ज़िन्दगी कैसे कटेगी। जब से उन्हें पता चला है कि डाक्टर के बजाय एक झोलाझाप ने ऑपरेशन कर उनकी किडनी निकाली है, तब से और चिंता बढ़ गई है।

दरअसल, गुजरात निवासी रघु के परिवार पर करीब दो वर्ष से दुखों का पहाड़ टूट रहा था। मां की बीमारी, बहन का तलाक, भाई भाभी के रिश्तों में खटास और इसकी वजह से पिता की परेशानी, पिता की नौकरी छूट जाना और परिवार का दाने-दाने को मोहताज हो जाना..आदि ने रघु को अंदर से तोड़ दिया था। पिता पर कर्ज़ का बोझ बढ़ रहा था। तगादा के दौरान लोग पिता को अपमानित करने लगे, लेकिन चाहकर भी रघु कुछ नहीं कर सके। यह सब रघु बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और एक आत्महत्या की ठान ली। हालांकि, ईश्वर को यह मंज़ूर नहीं था। रोजी रोटी की तलाश में हिमाचल, फिर दिल्ली पहुंचे रघु को एक दिन विपिन व शैलेष मिल गए। रघु ने इनसे नौकरी दिलाने की बात की। बातों-बातों में रघु ने अपना अतीत इनके सामने खोल दिया। आरोपितों ने रघु से हमदर्दी दिखाते हुए उसकी मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने रघु का एक यूनिट रक्त 1200 रुपये में डोनेट करवाया। बाद में पता चला कि यह रक्त भी उन्होंने हरियाणा के सोनीपत के गोहाना वाले अस्पताल के लिए लिया गया था। इसके बाद आरोपितों ने कहा कि 1200 रुपये में क्या होगा। अपनी किडनी किसी ज़रूरतमंद को दान कर दो। उसके बदले तीन लाख रुपये मिल जाएंगे। रघु ने विरोध किया तो दोनों ने कहा कि पुण्य का काम है। किडनी दान करके तुम किसी को नया जीवन दे सकते हो, पुण्य कम सकते हो। दोनों रघु से मिलकर लगातार उसे समझाने में जुटे चूंकि शेलैष और विपिन भी अपनी किडनी बेच चुके थे। ऐसे में उन्होंने अपने ऑपरेशन के निशान दिखाते हुए कहा कि एक किडनी पर ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। आरोपितों ने उसे कई और किडनी डोनर से मिलवाया और यह विश्वास दिलाया कि एक किडनी निकलवाने पर भी ज़िन्दगी खतरे में नहीं आती। आरोपितों ने विश्वास जीतने के लिए छह हजार रुपये रघु के पिता के बैंक खाते में भेज दिए। उसके बाद तीन लाख रुपये में किडनी देने का सौदा हो गया। इसके बाद आरोपितों ने उसे एक सप्ताह तक पश्चिम विहार और हौजरानी के फ्लैटों में रखा।❑❑

संपादकीय

शांति मिशन

परवानों को बुलाते हैं शमां दिखा के हम

गाँधीवादी सिद्धांतों व विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक दुर्भाग्यवश अनेक बार विभाजित हो चुकी है। ब्रह्मानंद रेड्डी से लेकर बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदर बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, मोहसिना किदवई, देव राज अर्स, ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे और भी अनेक बड़े से बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्ट से समय समय पर किसी न किसी मतभेद के चलते अपना नाता तोड़ा। परंतु चूंकि यह नेता गांधीवादी व धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर चलने वाले तथा व्यक्तिगत जनाधार रखने वाले नेता थे, लिहाज़ा इन्होंने सत्ता हासिल करने के लिये किसी धुर विरोधी विचारधारा की दक्षिणपंथी पार्टी में शामिल होने के बजाय स्वयं अपना संगठन खड़ा किया। परंतु वर्तमान दौर में जबकि बेरोज़गारी व महंगाई अपने चरम पर है देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार पर है। डॉलर के मुक़ाबले रुपया अपने रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुका है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी साख बचाने के केवल दो ही उपाय हैं जिनके सहारे वह जनता में विशेषकर देश के बहुसंख्यक समाज में लोकप्रिय बनने रहने की कोशिश कर रही है। एक तो मुख्यधारा क मीडिया विशेषकर टीवी चैनल्स को अपने पक्ष में कर सत्ता के कसीदे पढ़वाना और समाज को धर्म के आधार पर विभाजित करने की पुरी छूट देना और दूसरे विवादित अविवादित धार्मिक मुद्दों को हवा देकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को उकसाकर तथा धार्मिक विवाद पैदा कर धर्म आधारित ध ुवीकरण कर बहुसंख्यकवाद की राजनीति करना।

भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पर चलते हुए भले ही स्वयं को संख्याबल के हिसाब से मज़बूत स्थिति में क्यों न पा रही हो परंतु देश का एक बड़ा वर्ग विशेषकर पढ़ा लिखा, गंभीर चिंतन करने वाला वर्ग, उदारवादी समाज यहां तक कि विदेशी मीडिया व उनके विदेशी राजनेता भी भारतीय राजनीति की वर्तमान शैली की आलोचना करते रहते हैं। इस वर्ग का मानना है कि जो भारतवर्ष गांधी का भारत कहा जाता है, जिस गांधी के सत्य, अहिंसा के सिद्धांत की पूरी दुनिया कायल हो, अनुसरण रही हो, उस देश में गांधी के हत्यारे गोडसे की विचारधारा का पनपना और सत्ताधारी नेताओं व उनके समर्थकों द्वारा गोडसे का गुणगान किया जाना आख़िर क्या संदेश दे रहा है? और इसी संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह कि उपरोक्त हालात के बावजूद आख़िर क्या वजह है कि एक और जहां सत्ताधारी दल के कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी तक यह महसूस कर रहे हों कि 'स्वस्थ' लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मज़बूत होना जरूरी है और यह उनकी ईमानदारी से अच्छा है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत बने।

लोकतंत्र दो पहियों के सहारे चलता है जिनमें से एक पहिया सत्ताधारी पार्टी है जबकि दूसरा पहिया विपक्ष है। लोकतंत्र के लिए मज़बूत विपक्ष की ज़रूरत है और इसलिए मैं हृदय से महसूस करता हूं कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत होना चाहिए।' गडकरी का यह भी कथन है कि –'चूंकि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, अन्य क्षेत्रीय पार्टियां उसका स्थान ले रही है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि एक अन्य क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस का स्थान लें। प्रश्न यह है कि जब सत्ता पक्ष का एक कद्दावर नेता व केन्द्रीय मंत्री कांग्रेस के बारे में ऐसी उम्मीद व विचार रख रहा हो ऐसे में क्या वजह है कि आये दिन कांग्रेस का ही कोई न कोई मुख नेता किसी न किसी बहाने से न केवल कांग्रेस छोड़ रहा है बल्कि कांग्रेस की धुर विरोधी विचारधारा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो रहा है? वे कांग्रेसी नेता जो संसद से सड़कों तक भाजपा को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संरक्षण में चलने वाली सांप्रदायिक, नाजीवादी, गांधी की हत्यारी, गोडसे का गुणगान करने वाली देश को धर्म जाति भाषा आदि के नाम पर विभाजित करने वाली तथा अंग्रेज़ों से मुआफी मांगने वाले नेताओं की पार्टी बताया करते थे, क्या वजह है कि आज वही नेता उसी भाजपा में शामिल हो रहे हैं?

एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है आज के दौर में कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने वाले नेताओं में गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने अथवा वैचारिक प्रतिबद्धता नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। न ही उनमें इतना दम है कि वे अपने बल पर कोई नया राजनैतिक संगठन खड़ा कर सकें। इनके लिये इससे भी महत्वपूर्ण उनका राजनैतिक भविष्य अर्थात् सत्ता में बने रहना है। यही वजह है कि कल तक गांधीवादी विचारधारा की माला जपने वाले और संघ व भाजपा को पानी पी-पी कर कोसने वाले सुष्मिता देव, रीता बहुगुणा जोशी, हेमंत विस्वा सरमा, मणिक साहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आर.पी.एन. सिंह जैसे और भी कई नेता और पिछले दिनों सुनील जाखड़ जैसे नेता उसी भाजपा में शामिल हो गये।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो मध्य प्रदेश में अपने समर्थकों विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार तक गिरा दी और राज्य में भाजपा सरकार बनने का रास्ता साफ किया। ज़ाहिर है जब कांग्रेस पार्टी में ही ऐसे रीढ़ विहीन सिद्धांत विहीन तथा विचार विहीन सत्ताभोगी नेताओं की भरमार हो तो कांग्रेस को रसातल में जाने से भला कौन बचा सकता है। कांग्रेस और भाजपा के इस अंतर से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने गठन से लेकर अब तक पार्टी विभाजन में कीर्तिमान स्थापित किये हैं और नेताओं के दल-बदल व पलायन में भी रिकॉर्ड बनाये हैं वहीं भाजपा, जनसंघ से लेकर आज की भाजपा तक कभी विभाजित नहीं हुई और नेताओं के पार्टी छोड़ने का भी सिलसिला नाम मात्र ही रहा। नि:संदेह भाजपा इस मामले में अति अनुशासित कैडर्स पर आधारित पार्टी है। उत्तरांचल, गुजरात, त्रिपुर जैसे विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्रियों को रातों रात बदलने के बावजूद कोई नेता विद्रोही स्वर नहीं बुलंद कर सका। जबकि कांग्रेस में कमलनाथ बनाम सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिद्धू और अशोक गहलौत बनाम सचिन पायलट खींचतान के नतीजे सबके सामने हैं। कांग्रेस के नेताओं के भाजपा में शामिल होने की दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि भाजपा अपने अनुशासित कैडर्स पर भरोसा रखते हुए कभी आसाम में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुये हेमंत बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री पद दे देती है तो कभी त्रिपूरा में अपनी पार्टी के विप्लव कुमार देव को हटाकर कांग्रेस से ही भाजपा में आये माणिक साहा को रातों-रात मुख्यमंत्री बना देती हैं कभी मणिपुर में कांग्रेस से आये एन. बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री को केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करती है तो कभी रीता बहुगुणा को मंत्री बनाती या लोकसभा का टिकट देकर सांसद निर्वाचित कराती है तो कभी जतिन प्रसाद को मंत्री बनाती है। इस तरह के और भी अनेक उदाहरण है जिनसे पता चलता है कि भाजपा के इस तरह के आकर्षक 'ऑफर्स' भी कांग्रेस नेताओं के लिये भाजपा की पनाहगाह बनने में सहायक साबित हो रहे हैं। हर सिद्धांत व विचारविहीन नेता यही सोचता है कि भाजपा में जाते ही सत्ता हासिल हो जायेगी। गोया भाजपा अपनी रणनीति में सफल दिखाई देती है कि बक़ौल शायर 'परवानों को बुलाते हैं शम्मा दिखा के हम।' □□

जन्नत अर्ज़ी में तीन दिन

डॉ मौलाना सईदउद्दीन कासमी
(सदस्य मजलिस आमला जमीअत उलेमा हिन्द)

3

बाप-बेटों के संयुक्त कारोबार की विशेष सूरतों की तल्खीस हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला माअरूफ़ी उस्ताद दारूल उलूम देवबंद ने पेश की और फिर इस पर मुनाकशा हुआ। इसी तरह मेडिकल इंश्योरेंस की तलखीस पेश की गयी और इस पर मुनाकशा हुआ और मुफ्तियाने कराम को खुलकर अपना दृष्टिकोण पेश करने की दावत दी गयी। मुनाकशा के बाद प्रस्ताव कमेटी अहम मुफ्तियाने कराम पर आधारित बना दी गयी और शाम का समय प्रस्ताव बनाने के लिए दिया गया।

तीन बजे पर्यटन स्थल वुलर वेन्टेज पर चाय के लिए निमंत्रित किया गया था इसलिए बसों के माध्यम से सभी वहां पहुंचे। हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर्रहमान खैराबादी और मुफ्ती हबीबुर्रहमान आज़मी अगरचे नकाहत की वजह से तैयार न थे मगर हम लोगों के इसरार पर तैयार हो गए, हज़रत मुफ्ती हबीबुर्रहमान खैराबादी को यह ख़ादिम सहारा देकर ऊंची चट्टान तक ले गया और क़ुदरती मंज़रों का नज़ारा कराया। चायनोशी से फारिग़ होकर अस्र की नमाज़ वहीं जमआत से अदा की गयी। और फिर यह क़ाफ़िला मदरसा रहीमिया वापस आया।

चौथा चरण हज़रत मौलाना रहमतुल्ला की अध्यक्षता में मग़रिब की नमाज़ के बाद तिलावते कलामउल्ला और मौलाना अहमदुल्ला की नआत से आगाज़ हुआ। इस चरण को विद्वान् उलमा व मुफ्तियान के विचार और वर्तमान समस्याओं पर मुफ्ती हज़रात को ध्यान दिलाने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें हज़रत मौलाना शफीक अहमद बड़ोदवी, मौलाना इफ्तेख़ार अहमद अध्यक्ष जमीअत उलेमा कर्नाटक, मौलाना इब्राहीम तारापुरी इंग्लैंड, मौलाना सद्दीक़ुल्लाह चौधरी पश्चिमी बंगाल, मौलाना शमीम अशरफ़ दुबई, मौलाना ज़ैनुल आबेदीन गुजरात, डाक्टर मुफ्ती अब्दुल रहमान मुंगेरा इंग्लैंड, मौलाना मतीनुल हक़ ओसामा कासमी कानपुर, मौलाना अब्दुल्ला मीर कश्मीर ने अपने विचार रखे और आख़िर में मौलाना सैयद महमूद मदनी ने एक निकाह पढ़ाया और उनकी दुआ पर ही इस चरण का समापन हुआ।

पांचवीं और आख़िरी चरण हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू अल क़ासिम नौमानी मोहतमिम दारूल उलूम देवबंद की अध्यक्षता में क़ारी-ए-आसाम की तिलावत, मौहम्मद रमज़ान टोटा, शौक़त कश्मीरी और अहमद अब्दुल्ला की नात के बाद मौलाना सलमान मंसूरपुरी की निज़ामत में शुरू हुआ, मेडिकल इंश्योरेंस पर आयोजित की गयी तजवीज़ जिसमें कुछ इश्तशनाई सूरतों को छोड़कर सरकार की ओर से किया गया इंश्योरेंस, अस्पतालों से दिए गए पैकेज और इज़तरारी हालतों में इस्फादा करने की इजाज़त दी गयी है, हज़रत मौलाना रियासत अली बिजनौरी उस्ताद हदीस दारूल उलूम देवबंद ने पढ़कर सुनायी और कुछ नसाह भी फरमाए।

दूसरा प्रस्ताव बाप बेटों के बीच संयुक्त कारोबार की सारी स्थितियों पर आधारित प्रस्ताव जिसमें हर स्थिति को ख़त्म किया गया था और किन-किन शक्लों में बेटियां भी विरासत में शामिल होंगी इसकी सराहत की गयी थी। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मारूफ़ी ने पढ़कर सुनायी। प्रस्तावों के मूल में उचित परिवर्तनों को शामिल करके हज़रत मौलाना सलमान मंसूरपुरी ने हाउस से पास कराया।

सत्र के बीच पूर्व की बैठकों की तरह अनेक बार मुन्तजमीन की ओर से मीठी फीकी, जाफरानी दूधियाई चाय से मेहमानों की ज़ियाफ़त कश्मीरी मेवों, बादाम, अखरोट किशमिश, पिस्तें के साथ की जाती रही, साथ ही विभिन्न क़िस्मों के बिस्कुट भी पेश हुए जो कश्मीरी मुसलमानों की फराख़दिली और उच्च मेहमाननवाज़ी का सबूत और इख़्लास का नमूना पेश कर रही थी।

कार्यकर्ता जानते हैं कि कुछ भी हो जाए

गांधी परिवार पार्टी विचारधारा से समझौता नहीं करेगा

अजय माकन

पूर्व केन्द्रीय मंत्री अजय माकन राहुल गांधी के प्रिय पात्र हैं, कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य होने के साथ ही वे राजस्थान के प्रभावी महासचिव भी है जो उन दो राज्यों में से एक है जहां पार्टी सत्ता में है। एक बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट पार्टी के युवा नेताओं के लिए खुद को साबित करने का अवसर हो सकता है।

प्रश्नः- कांग्रेस अस्तित्व के संकट में क्यों फंसी है?

उत्तरः- इसमें दोराय नहीं कि हाल के दिनों में हमारा चुनावी प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। लेकिन हमें खत्म हुआ मानना मुर्खता होगी। 2019 के आम चुनाव में हमें 19.05 प्रतिशत वोट मिले थे, जब भाजपा 2009 में 18.08 प्रतिशत तक गिरकर आज जैसी मजबूत स्थिति में पहुंच सकती है, तो आप कांग्रेस के लिए 'अस्तित्व का संकट' जैसे वाक्यांश का उपयोग कैसे कर सकते हैं? हम देश के सबसे पुरानी राजनैतिक दल हैं जो पारंपरिक राजनैतिक शैली में काम करता है और अतीत में यह शैली काफी सफल रही है लेकिन समय बदल गया है, लोकतंत्र के उपकरणों का विकास होने के साथ मतदाताओं से संवाद का तरीका भी बदल गया है। निजी तौर पर मुझे लगता है कि पिछले दो दशकों में

अधिकांश कार्यकर्ता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते है, गांधी परिवार हमारा नेता है क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन पर पूरा भरोसा है और हमारा विश्वास है कि वे किसी भी स्थिति में इस महान राष्ट्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी की विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे।

बदलाव की इस चुनौती का जवाब देने में हम अपने विरोधियों की तुलना में धीमे थे। इसके अलावा, अगर हम विश्व स्तर पर रुझानों को देखें तो पाएंगे कि वैचारिक रूप से दक्षिणपंथी रुझान वाले राजनैतिक दल जीत रहे हैं, भारत इन प्रवृत्तियों से अछूता नहीं रह सकता।

प्रश्नः- अगले कुछ विधान सभा चुनावों और 2024 में आप कांग्रेस का कैसा भविष्य देखते हैं..?

उत्तरः- चुनाव जीतने के लिए जो भी ताक़त लगानी होती है, हम लगाते हैं, अंततः यह विचारों की लड़ाई है, यह उन लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश है जिनके अधिकार अपने बहुमत के बल पर सत्ता के मद में चूर अधिनायकवादी सरकार ने छीन लिए हैं।

प्रश्नः- बहुत से लोग कांग्रेस में नेतृत्व के मुद्दे की आलोचना कर रहे हैं? उनका कहना है कि गांधी परिवार पार्टी के लिए प्रासंगिक नहीं रहा, क्या ग़ैर गांधी व्यक्ति कांग्रेस का नेतृत्वकर्ता हो सकता है.?

उत्तरः- यह प्रश्न पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहते है, गांधी परिवार हमारा नेता है क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन पर पूरा भरोसा है और हमारा विश्वास है कि वे किसी भी स्थिति में इस महान राष्ट्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी की विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे।

प्रश्नः- युवा मतदाताओं का मत पाने के लिए उनसे कहने को कांग्रेस के पास क्या है.?

उत्तरः- अगर कोई युवा मतदाता इतिहास में बहुत गहराई तक नहीं जाना चाहता, तो भी मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा। मनमोहन सिंह और नरसिंहा राव के नेतृत्व में भारत सरकार का कामकाज शानदार था। हमने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया और आगे चलकर 14 करोड़ लोगों को ग़रीबी से बाहर निकाला। चाहे 1991 का आर्थिक संकट रहा हो या 2007 की मंदी, हमने इसका सफलता से सामना किया, अब इसकी तुलना भाजपा शासन से करें, मुद्रास्फीति, मूल्य, वृद्धि, बढ़ती असमानता और आर्थिक अनिश्चितता जैसे प्रश्नों का उत्तर वे बुलडोजर, लाउडस्पीकर, हिजाब और हनुमान चालीस की मदद से किए जा रहे ध्रुवीकरण से दे रहे हैं। बाकी के ख़िलाफ़ बहुसंख्यकों के ध्रुवीकरण के गंभीर परिणाम होंगे जिन्हें युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा।

प्रश्नः- कांग्रेस के पास राज्यों में युवा और उभरते हुए जन नेता न के बराबर हैं, आपके कई समकालीनों ने पार्टी छोड़ दी है जबकि बुजुर्ग नेताओं का श्रेष्ठतम समय ख़त्म हो चुका है?

उत्तरः- प्रतिकूलता सच्चे नेतृत्व

चाहे 1991 का आर्थिक संकट रहा हो या 2007 की मंदी, हमने इसका सफलता से सामना किया, अब इसकी तुलना भाजपा शासन से करें, मुद्रास्फीति, मूल्य, वृद्धि, बढ़ती असमानता और आर्थिक अनिश्चितता जैसे प्रश्नों का उत्तर वे बुलडोजर, लाउड स्पीकर, हिजाब और हनुमान चालीस की मदद से किए जा रहे ध्रुवीकरण से दे रहे हैं।

की परीक्षा है, दुर्भाग्य से मेरे कई समकालीन, जिन्हें हमारी पार्टी ने सालों तक महत्व दिया और विकसित किया, एक ऐसी पार्टी में शामिल होने के लिए हमें छोड़ गए जिसका राजनैतिक दृष्टिकोण हमसे उलट है लेकिन हम अब जिस स्थिति में हैं, वह युवाओं के लिए सीढ़ी चढ़कर ऊपर आने का मौक़ा है।

प्रश्नः- विपक्षी एकता की धुरी बनने की बजाए कांग्रेस पार्टियों को अलग-थलग कर रही है, ऐसा उन पार्टियों के नेताओं की महत्वकांक्षा के कारण है या उन लोगों के आरोपों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व के अहंकार के कारण.?

उत्तरः- आप और टीएमसी जैसी पार्टियाँ देश के विभिन्न हिस्सों में भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करती हैं अपने राज्यों के बाहर वे कांग्रेस के वोटों को बांटने के लिए चुनाव लड़ते हैं।❑❑

सरकार जैविक किसानों के लिए मार्केटिंग और मेहनताना बेहतर करने का प्रयास कर रही है : नरेन्द्र सिंह तोमर

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर स्वच्छ कृषि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं, उन्होंने भारत में प्राकृतिक और जैविक खेती को आगे बढ़ाने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया, पेश है नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्नः- प्रधानमंत्री मोदी और आपका मंत्रालय प्राकृतिक तथा जैविक खेती की क्षमता का लाभ उठाने पर काफी ज़ोर लगा रहे हैं, आप उसे कैसे पूरा करेंगे?

उत्तरः- प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती की ज़ोरदार वकालत की है, इससे देश में कृषि के इस रूप में प्रति जागरुकता बढ़ी हैं पिछले वर्ष दिसंबर में गुजरात के आणंद में वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हज़ारों किसानों के सामने प्रस्तुति दी थी। मंत्रालय की परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीआई) के तहत प्राकृतिक खेती अब 5 लाख हेक्टेयर खेतों में की जाती है।

प्रश्नः- अगले पाँच में देश का जैविक उत्पादन कहां तक पहुंचेगा, आपकी क्या राय? जैविक खेती की संभावनाओं को साकार करने के लिए आपका मंत्रालय किन क्षेत्रों में काम कर रहा है.?

उत्तरः- भारत ने जैविक खेती में मज़बूत और अभूतपूर्व प्रगति की है। आज देश जैविक खेती के क्षेत्र के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है और जैविक उत्पादों के मामले में सबसे ऊपर है। 2013-14 में जैविक खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र 11.08 लाख हेक्टेयर था और अब यह 38 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो गया है। मेरे मंत्रालय के पास वीकेवीआइ जैसी योजनाएं हैं और पूर्वोत्तर में जैविक खेती को बढ़ावा देने` लिए एक योजना है इससे 12 लाख हेक्टेयर में खेती कर रहे 15 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। गंगा के किनारे के 5 किमी के कॉरिडोर पर शुरुआती फोकस है। राज्यों को भी जैविक और प्राकृतिक खेती से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस मक़सद को हासिल करने के लिए हमने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और कार्य प्रगति पर है।

प्रश्नः- इसके लिए बाजार का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं..?

उत्तरः- जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों की बाजार तक पहुंच में सुधार लाने और उन्हें उपज का अच्छा पारिश्रमिक हासिल कराने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। उपज के प्रमाणीकरण के लिए, जैविक समूहों को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से जोड़ा जाना चाहिए जिनसे उन्हें कटाई के बाद की सुविधाएं सुनिश्चित हो सकें। अकेले पूर्वोत्तर के लिए अब तक 170 एफपीओ का गठन किया जा चुका है। इसके अलावा, पीकेवीवाई के तहत 130 एफपीओ शुरू किए गए हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को इन एफपीओ के ज़रिए बाजार से जोड़ने की योजना है।

प्रश्नः- प्रधानमंत्री मोदी फसलों से विविधीकरण के भी प्रबल समर्थक हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर और तिलहन तथा दलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उस दिशा में कदम के रूप में देखा गया। इसमें अब तक हमें क्या सफलती मिली है?

उत्तरः- सरकार नियमित रूप से 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य) तय करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्यों को दलहन, बाजरा, तिलहन, कपास आदि खरीदने के लिए मदद प्रदान की जाती है। केन्द्र और राज्य किसानों से 25 प्रतिशत तिलहन और दलहन खरीद रहे हैं। राज्यों की ओर से अतिरिक्त खरीदारी के प्रस्ताव को जल्द ही मंज़ूरी मिल जाती है। यह दालों के उत्पादन की मात्रा में पहले ही परिलक्षित हो रहा है। दलहन उत्पादन 2015-16 में 160.3 लाख टन था जो 2021-22 में बढ़कर 270 लाख टन हो गया है, यह 65 प्रतिशत की शानदार वृद्धि है। इसमें हमें आयात को 2016-17 में 63.6 लाख टन से घटाकर 2020-21 में 23.2 लाख टन करने में मदद मिली है।❑❑

जातिगत जनगणना की ओर बढ़ा बिहार

बिहार में सभी धर्मों के लोगों की जाति आधारित गणना जल्द शुरू होगी। इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली जाएगी। नई सदी में बिहार देश का दूसरा राज्य होगा, जो ऐसी गणना कराने जा रहा है। कर्नाटक में 2015 में यह गणना कराई गई थी, लेकिन उसने इसकी रिपोर्ट जारी नहीं की। राष्ट्रीय स्तर पर दो बार 1931 और 2011 में जाति आधारित जनगणना हो चुकी है। अभी भी अंग्रेज़ों के समय 1931 में हुई जातिगत जनगणना का ही इस्तेमाल आमतौर पर होता आया है, जबकि 2011 की जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति बनने के बाद राज्य मंत्रिपरिषद ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से यह गणना कराने का फैसला किया है।

ऐसी जनगणना के प्रतिकूल केन्द्र सरकार का तर्क यह रहा है कि 1931 में सिर्फ 24 जातियों के लोगों की गणना हुई थी, जबकि 2011 की गणना में 4,28,000 जातियों और उपजातियां सामने आई थीं। जनगणना के लिए कम्प्यूटर में इतने कॉलम बनाना संभव नहीं है, इसलिए यह गणना व्यावहरिक नहीं है। इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से समज में विद्वेष की आशंका भी जताती रही है। बावजूद अपने इन तर्कों के राज्य में जब जब ऐसी जनगणना की मांग उठी है, भाजपा ने राज्य स्तर पर प्रस्ताव का समर्थन ही किया है। जातिगत गणना कराने के पक्ष में राज्यों की विध ानसभाओं ने भी समय-समय पर प्रस्ताव पारित किए। बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों ने फरवरी 2019 और विधानसभा ने फरवरी 2020 में प्रस्ताव पारित किया। इसी तरह तेलंगाना ने अक्तूबर 2021 में विधान सभा से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र से जाति आधारित गणना कराने की मांग की। जब केन्द्र सरकार ने ऐसी गणना को अव्यावहारिक करार देते हुए सामान्य जनगणना का फैसला लिया, तब राजनीतिक दलों ने दबाव बनाने के लिए अपने-अपने तरीके से पहल की। बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने 23 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया कि देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। इसके अगले दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि 'अगर सभी पार्टियां सहमत हों, तो वह राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना के प्रस्ताव का समर्थन करेंगी।' लेकिन केन्द्र सरकार ने जब इस मांग को ठुकरा दिया, तब बिहार में सत्ता और विपक्ष ने राज्य स्तर पर गणना पर जोर दिया। ऐसी गणना में जातियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से सामने आने के तर्क को ख़ारिज करते हुए नीतीश कुमार ने दावा किया कि बिहार में बेहतर तरीक़े से इसे पूरा किया जाएगा।

जाति आधारित जनगणना का बहुत मुखर विरोध कहीं नहीं हुआ है। अब सभी राज्य इसे कराने पर विचार कर रहे हैं। राज्यों में यह हो जाएगा तो स्वत: राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े सामने आ जाएंगे। इसी तरह , बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसी जनगणना पर जोर देते रहे हें उनका तर्क है कि इससे एक वैज्ञानिक डाटा सामने आएगा और पता चलेगा कि कौन गरीब है।

पिछले दिनों ऐसी गणना को लेकर सियासी शास्त्रार्थ चल रहा था, तब 17 मई 2022 को भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी कर कहा कि भाजपा कभी इसके विरोध में नहीं रही है। भाजपा के गोपीनाथ मुंडे ने 2010 में लोकसभा में इस विषय पर चर्चा के दौरान प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस मुद्दे पर पटना में हुई सर्वदलीय बैठक में इस गणना पर सर्वसम्मति बनी, उसमें भाजपा शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित गणना कराने की बजाय ग़रीबों की गणना कराने पर ज़ोर देती रही है। बिहार में जाति आधारित गणना के साथ इसके लिए भी अलग से कॉलम रखने का फैसला लिया गया हे। दूसरी बात, सभी धर्मों में जाति, आधारित गणना का तर्क वह देती रही है, बिहार में यह भी होने जा रहा है।

अब देश में कुल मिलाकर जो आधिकारिक स्थिति है, उसमें कोई भी जाति राज्य आधारित गणना कराने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी गणना के समर्थक राजनीतिक दलों के अपने-अपने तर्क हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि जातिगत जनगणना ज़रूरी है इससे यह जानकारी हो जाएगी कि किन- किन जातियों में कितनी कितनी आबादी है। इसके बाद पिछड़ी जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुसार योजनाएं चलाई जा सकेंगी। आबादी के अनुरूप उस जाति विशेष के उत्थान के लिए सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे सकेगी। जातिगत जनगणना पूरी होने के बाद यह भी पता चलेगा कि कौन ग़रीब है?

ध्यान देने की बात है कि जाति आधारित जनगणना का बहुत मुखर विरोध कहीं नहीं हुआ है। अब सभी राज्य इसे कराने पर विचार कर रहे हैं। राज्यों में यह हो जाएगा तो स्वत: राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े सामने आ जाएंगे। इसी तरह, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसी जनगणना पर जोर देते रहे हें उनका तर्क है कि इससे एक वैज्ञानिक डाटा सामने आएगा और पता चलेगा कि कौन

बाक़ी पेज 11 पर

बैंकिंग और फाइनेंस में कैरिअर की राह

आज भारत में बैंकिंग सेक्टर का इतना विस्तार हो गया है कि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की 67 हज़ार से अधिक शाखाएं काम कर रही हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही हैं कि 2040 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग हब बन जाएगा। ख़बर यह है कि साल के अंत तक तकरीबन 40 हजार लोग रिटायर भी हो सकते हैं। इनमें हर सेक्टर के लिए अलग अलग कर्मचारियों की मांग है। जैसे इंटरनेशनल बैंकिंग के सेक्टर एनआरआई बैंकिंग ऑफिसर, इंटरनेशनल ट्रेड, ऑफिसर, फोरेक्स ऑफिसर। बिजनेस बैंकिंग के सेक्टर में कॉपोरेट बैंकिंग आफिसर, क्रेडिट ऑफिसर, कैश मैनेजमंट आफिसर। फाइनेंशियल रिसर्च के सेक्टर में फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिट। ब्रांच बैंकिंग के सेक्टर में पर्सनल बैंकर, वेल्थ एडवाइजर, लोन ऑफिसर के लिए विकल्पों की भरमार हैं एचडीएफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, कोटक महिन्द्र बैंक जैसे निजी बैंक हैं, वहीं सरकारी बैंकों ने भी युवाओं के लिए ढेरों अवसर तैयार किए हैं। इसी के मद्देनज़र अब सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा जैसे कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी प्रचलन में आ गए हैं। ये कोर्स प्राइवेट बैंकों में कैरिअर की राह, आसान तो करते ही हैं सरकारी बैंकों में भी पीओ, क्लर्क, आरबीआई ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे छात्रों को भी बैंकिंग की बारीकियां जानने का मौक़ा देते हैं।

अलग-अलग सेक्टर्स का कार्य

एनआरआई बैंकिंग ऑफिसर भारत या विभिन्न देशों की विदेशी शाखाओं में स्थानीय शाखाओं से बैंक के एनआरआई ग्राहकों को संभालने की ज़िम्मेदारी होती हैं बैंकिंग परिचालन और विदेशी मुद्रा सेवाओं के अलावा वे इन एनआरआई ग्राहकों के लिए भारत में निवेश सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं।

इंटरनेशनल ट्रेड ऑफिसर

इंटरनेशनल ट्रेड ऑफिसर का काम व्यापार का विकास और दो देशों के बीच गुड्स एण्ड सर्विसेज के लेन-देन और गठजोड़ को बढ़ावा देना होता हैं जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है यह भी देखना अधिकारी की ज़िम्मेदारी होती है।

फोरेक्स ऑफिसर

फोरेक्स ऑफिसर बैंकों और ग्राहकों की तरफ से विभिन्न और विदेशी मुद्राओं की लेन-देन को संभालने का काम करते हैं। जब कोई बैंक ग्राहक विदेशी मुद्रा को खरीदना या बेचना चाहता है तब उस मुद्रा का सही मूल्य ग्राहक को समझाने का काम भी फोरेक्स ऑफिसर का होता है।

कॉपोरेट बैंकिंग ऑफिसर

कॉपोरेट बैंकिंग ऑफिसर व्यापार और बड़ी कंपनियों के ग्राहकों के लिए नियमित रूप से बैंकिंग परिचालन में विशेष रूप से डिजाइन के उत्पाद उपलब्ध कराने का काम करता है। यह सैलरी और करंट अकाउंट वाले ग्राहकों से भी अच्छे संबंध बनाये रखने के लिए भी ज़िम्मेदार होता है। इसके अलावा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, क्रेडिट रिसर्च एनालिस्ट, पर्सनल बैंकर, वेल्थ एडवाइजर, लोन ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर कैश मैनेजमेंट ऑफिसर एवं फाइनेंशियल एनालिस्ट पद के हैं।

पाठयक्रम के बारे में

टीकेडब्लूएस इंस्टीटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस के डायरेक्टर के मुताबिक ग्लोबल पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग एण्ड फाइनेंस एक वर्ष का कोर्स है। इसके तहत बैंकिंग ऑपरेंशस, धन प्रबंधन, ट्रेड फाइनेंस, फोरेक्स, फाइनेंस एसएमई जैसे विषय पढ़ाया व सिखाया जाता है।

योग्यता

स्नातक और किसी भी स्ट्रीम से अंतिम वर्ष के छात्र इस कोर्स में आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थी के स्नातक में कम से कम 50 प्रतिशत है वह भी इस कोर्स में आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

कैरिअर और प्लेसमेंट

इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद विद्यार्थी को इंटरनेशनल बैंकिंग, फोरेक्स और ट्रेजरी, कापोरेट, लोंस, फाइनेंशियल रिसर्च संबंधित बड़ी ब्रांडों से ऑफर मिलने लगते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स अलग अलग स्किल्स के बच्चों को अच्छी सैलरी पर नियुक्त करते हैं। सार्वजनिक बैंक ज़्यादातर अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा के आधार पर क्लर्क और परिवीक्षाधीन अधिकारी के पदों के लिए नियुक्तियां करते हैं।

प्रमुख संस्थान

इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, www.ignou.nic

इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली। www.ipu.ac.in

टीकेडब्ल्यूएस इंस्टीटयूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंस, नई दिल्ली। www.tkwsibf.org

मणिपाल यूनिवर्सिटी, कर्नाटक www.manipal.edu

सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मुम्बई, महाराष्ट्र। www.siu.edu.in

इस्लामी दुनिया

ईरान में पटरी से यात्री ट्रेन

पूर्वी ईरान में पिछले दिनों एक एक्सकवेटर से टकराकर एक यात्री ट्रेन पटरी से उतरने गई, जिससे कम से कम 22 लोगों की मौत होने की सूचना है और 50 के करीब लोगों के घायल होने की सूचना है। अधिकारियों के अनुसार, सरकारी इस्लामिक रिपब्लिक रेलवे द्वारा संचालित ट्रेन तेहरान से लगभग 550 किमी दक्षिण पूर्व स्थित ताबास से यज्द शहर जा रही थी। इस ट्रेन में 350 व्यक्ति सवार थे।

पैगंबर साहब की बेटी पर आधारित फिल्म की स्क्रीनिंग रद्द

ब्रिटेन की सबसे बड़ी सिनेमा कंपनी में शुमार सिने वर्ल्ड ने ब्रिटिश मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन के बाद आगामी विवादित फिल्म की सभी स्क्रीनिंग रद्द कर दीं। फिल्म के बारे में दावा किया है इसमें पैगंबर मुहम्मद साहब की बेटी की कहानी दिखाई गई है। सिने वर्ल्ड ने एक बयान में कहा कि उसने कर्मचारियों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'द लेडी ऑफ हेवन' की स्क्रीनिंग रद्द करने का निर्णय लिया।

इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद विवाह कार्यक्रमों पर रोक

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार ने बिजली बचाने के प्रयासों के तहत इस्लामाबाद शहर में रात 10 बजे के बाद विवाह कार्यक्रमों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई। जियो न्यूज के खबर के अनुसार भीषण बिजली संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान ने बिजली की खपत को कम करने के लिए कई क़दम उठाए हैं और अब इस्लामाबाद में रात 10 बजे बाद विवाह समारोहों पर पाबंदी रहेगी जो 8 जून से प्रभावी है।

तालिबान ने धार्मिक आरोपों के चलते मॉडल को हिरासत में लिया

इस्लामाबाद : तालिबान ने इस्लाम और कुरआन के अपमान के आरोप में अफग़ानिस्तान के एक मशहूर फैशन मॉडल और उनके तीन साथियों को हिरासत में ले लिया। तालिबान के खुफिया महानिदेशालय ने टवीटर पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें फैशन मॉडल अजमल हक़ीकी के हाथों में हथकड़ी लगी दिखाई देती है। व्यापक रूप से प्रसारित और विवादास्पद वीडियो में अजमल हक़ीक़ी के सहयोगी गुलाम सखी कुरआन की अरबी आयतों को हास्यपूर्ण आवाज के साथ बोलते हैं, जिस पर हक़ीक़ी को हंसते हुए देखा जा सकता है। सखी समेत तीन अन्य साथियों के साथ मौजूद अजमल हक़ीक़ी ने कहा, मैं अफ़ग़ानिस्तान के लोगों, आदरणीय धार्मिक विद्वानों और इस्लामी अमीरात से माफ़ी मांगता हूं।'

रघु ठाकुर

युद्ध के हासिल और सवाल

हिंसा और युद्ध भयावहता कौन नहीं जानता? इनका सबसे बड़ा इतिहास तो धार्मिक ग्रंथों और कहानियों में ही मिलता है। लगभग सभी धर्मों में कुछ एक अपवाद छोड़कर आपस में अपने-अपने मतों या पंथों की श्रेष्ठता को लेकर युद्ध हुए हैं। साम्राज्य के मोह में भी दुनिया में बहुत से युद्ध हुए। युद्ध करने वाले एक ही मज़हब के रहे या भिन्न मज़हब के, इस पर विमर्श संभव है, लेकिन आमतौर पर विपरीत मतों को युद्धों के माध्यम से परास्त करने के उपक्रम होते रहे हैं।

अभी तक का तथ्य तो यही है कि युद्ध ने दुनिया और सभ्यता को नुकसान तो बहुत पहुंचाया, परंतु कोई भी ताकतवर अपने से भिन्न मत या कमज़ोर शक्ति वाले को समाप्त कभी नहीं कर पाया। भारत के अतीत में देखें तो कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध हुआ, पर भगवान माने जाने वाले कृष्ण की जीत के बाद भी जरासंध के अनुयायी या मानने वाले अभी भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के बीच युद्ध हुए, मगर आज भी दोनों ही मतों को मानने वाले मौजूद हैं। लाखों लोग मारे गए। शिया और सुन्नी सम्प्रदाय के बीच युद्ध हुए इसके बाद भी दोनों मत को मानने वालों की तादाद कम नहीं है।

कहने का तात्पर्य यह है कि युद्ध या हिंसा न किसी दूसरी विचार धारा या पंथ को समाप्त कर सकी है, न कर सकेगी। प्रथम विश्वयुद्ध में मरने वालों की संख्या एक करोड़ से अधिक थी, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या साढ़े पांच करोड़ से ज़्यादा रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में करीब साढ़े तीन करोड़ लोग ज़ख्मी हुए थे और 1940 के दशक में तीस लाख लोग लापता हो गए थे। धर्म के नाम पर जो युद्ध हुए, उनसे विजेता और पराजित दोनों पक्ष युद्ध के पहले भी रहे और युद्ध के बाद भी। कोई पक्ष अपने प्रतिपक्ष को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सका। यानि युद्धों की जीत और हार न स्थायी हुई है, न होगी।

रंगभेद और नस्लभेद के नाम पर दुनिया में कई युद्ध और गृहयुद्ध हुए। पर अन्तिम निर्णय के दृष्टिकोण को स्वीकार करें तो इनका परिणाम शून्य है। इसके बावजूद दुनिया के सभ्य कहे जाने वाले मुल्क या समुदाय युद्ध क्यों करते हैं, यह खोज का विषय भी है और समझने का भी। एक विदेशी इतिहासकार ने दुनिया के इतिहास और युद्धों का अध्ययन कर बताया कि पिछले लगभग साढ़े तीन हजार सालों में दो सौ साठ वर्ष ही ऐसे रहे हैं जिनमें कोई युद्ध नहीं हुए है इसलिए मन मस्तिष्क में यह प्रश्न तो कौंधता ही है कि यदि दुनिया में युद्ध नहीं होते तो दुनिया कैसी होती? कितनी विकसित होती? सभ्यता और सम्पन्नता का रूप कितना भव्य होता? विज्ञान कितना उन्नत होता? ये सब विचारणीय विषय है?

लेकिन इस 21वीं शताब्दी में एक और फर्क नज़र आ रहा है। युद्ध अब विनाश और क्रूरता की सभी हदें लांघ रहे हैं। प्राचीन काल के युद्धों में एक अलिखित मर्यादा थी कि अंधकार होने या शाम होने के बाद युद्ध रोक दिए जाते थे। युद्ध सैनिकों में होता था, शास्त्रों से होता था, पर विजेता सेना आमजन को तबाह नहीं करती थी। चाहे रामायण-महाभारत के समय के युद्धों को देखें या उसके बाद के कुछ समय तक यह परंपरा क़ायम रही। विदेशी मुग़ल हमलावर जो वास्तव में आरंभिक दौर में लुटेरे जैसे थे, उन्होंने इन परंपराओं को तोड़ा। चंगेज ख़ा ने जब दिल्ली पर कब्ज़ा किया तब कई लाख लोगों को मारा और लूटा। निहत्थी जनता के क़त्लेआम, बर्बरता और लूट की शुरूआत इसी प्रकार हुई। दूसरे विश्व युद्ध में दुश्मन राष्ट्रों को हराने के लिए मित्र राष्ट्रों की ओर से अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए और हिरोशिमा व नागासाकी को तबाह कर दिया। जहां इस हमले से एक ओर हिटलर और उनके सहयोगियों को जवाब दिया गया और नाजी सेनाओं के मनोबल को तोड़कर युद्ध जीता गया, वहीं यह भी एक अमानवीय और मर्यादित युद्ध की ज़्यादा भयावह शुरूआत थी हालांकि बाद में लीग ऑफ नेशंस और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी युद्ध के लिए चार्टर बनाया था और नियम तय किए थे। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है और आर्थिक मामलों में वह बड़े देशों पर ही निर्भर है, इसलिए उसके द्वारा निर्धारित और स्वीकृत मापदंड कमजोर देशों पर तो लागू हो जाते हैं, पर शक्तिशाली देश उन्हें नहीं मानते। दुनिया का जितना पैसा अभी तक युद्धों पर ख़र्च हुआ है, उसकी गणना अगर की जाए तो इतने पैसे में एक नहीं, कई दुनिया खड़ी हो सकती थी।

युद्ध या हिंसा न किसी दूसरी विचार धारा या पंथ को समाप्त कर सकी है, न कर सकेगी। प्रथम विश्वयुद्ध में मरने वालों की संख्या एक करोड़ से अधिक थी, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में मरने वालों की संख्या साढ़े पांच करोड़ से ज़्यादा रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में करीब साढ़े तीन करोड़ लोग ज़ख्मी हुए थे और 1940 के दशक में तीस लाख लोग लापता हो गए थे। धर्म के नाम पर जो युद्ध हुए, उनसे विजेता और पराजित दोनों पक्ष युद्ध के पहले भी रहे और युद्ध के बाद भी। कोई पक्ष अपने प्रतिपक्ष को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सका। यानि युद्धों की जीत और हार न स्थायी हुई है, न होगी। रंगभेद और नस्लभेद के नाम पर दुनिया में कई युद्ध और गृहयुद्ध हुए। पर अन्तिम निर्णय के दृष्टिकोण को स्वीकार करें तो इनका परिणाम शून्य है। इसके बावजूद दुनिया के सभ्य कहे जाने वाले मुल्क या समुदाय युद्ध क्यों करते हैं, यह खोज का विषय भी है और समझने का भी।

अब रूस ने यूक्रेन पर युद्ध थोपा है। वह कितना क्रूर और भयावह है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भले ही संयुक्त राष्ट्र के नियम कहते हों कि आवासीय क्षेत्र या निहत्थे लोगों पर हथियार इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, पर रूस यूक्रेन को घुटने टेकने के लिए नागरिक क्षेत्रों पर लगातार बम बरसा रहा है। लगभग पचास लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर गए हैं और शरणार्थी जीवन जी रहे हैं। निहत्थे नागरिक जिनका कोई हाथ न युद्ध के कराने में हैं, न जिनकी कोई युद्ध की आकांक्षा, वे सभी इस युद्ध का शिकार हो रहे हैं। हज़ारों बच्चे मारे गए हैं। युद्ध के नाम पर यह क्रूरता अभूतपूर्व हैं तीन माह हो चुके हैं जंग को चलते हुए, पर इसका अंत नज़र नहीं आ रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह युद्ध दुनिया को नए सामरिक संतुलन व संगठन बनाने के लिए थोपा गया है। साथ ही एक और नए शीत युद्ध की शुरूआत भी इससे हो गई है।

यूक्रेन का झुकाव अमेरिका और नाटो की ओर था और रूस इसे अपनी सुरक्षा और संपन्नता के लिए बिल्कुल भी मानने को तैयार नही था। रूस पर अब तक लगाए गए तथाकथित प्रतिबंध भी कोई परिणाम नहीं दे सके हैं। नाटों देशों की ओर से यूक्रेन को दी जा रही आर्थिक और सामरिक सहायता से युद्ध अनिर्णय की दिशा में बढ़ता जा रहा है। किसी की जीत हार होती नहीं दिख रही है पर युद्ध जितना लंबा खिंचता जा रहा है, उसकी उतनी ही पीड़ा मानवता को भोगनी पड़ रही है। लड़ाई तो नाटो और रूस की है और अपने- अपने दबदबे के लिए है, पर मारे तो वे निर्दोष लोग जा रहे हैं जिन्हें शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि युद्ध होता क्या है, और किसलिए हो रहा है..?

रूस-चीन और तटस्थता के नाम पर छिपी पक्षधरता जैसी भूमिका में भारत इस नए सैन्य ब्लॉक में अघोषित-अलिखित सहयोगी बना है। माना जा सकता है कि भारत की नीति और चिंताएं पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर और भविष्य की राष्ट्रीय संभावनाओं को लेकर हैं। परंतु भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, वह शायद ही कभी चीन को ईमानदारी से भारत के साथ रहने देगा। बल्कि दूसरी ओर एक और ख़तरा है कि भविष्य में कहीं भारत दोनों गुटों से अलग थलग होकर किसी और बड़े नुकसान का शिकारन हो जाए।

कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि वैश्विक संस्थाएं वैश्विक ताक़तों की पिछल्लगू बन कर रह गई है। दुनिया को युद्धों, विवादों और आर्थिक शोषण से मुक्ति का वही रास्ता है जो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने बताया था, और जिसे एक कार्यक्रम के रूप में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने बालिग मताधिकार से निर्वाचित विश्व संसद की कल्पना प्रस्तुत की थी। लोहिया की सप्त क्रांतियों में एक क्रांति विश्व संसद के निर्माण की है।❑❑

राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ता रुझान चिंताजनक

विपिन पब्बी

प्रत्येक चुनावों से पूर्व विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार बड़े-बड़े वायदे करते हैं। ऐसे अधिकांश वायदे तथा आश्वासन बिना पूरे हुए रह जाते हैं तथा अब आम लोगों ने ऐसे वायदों को गंभीरतापूर्वक लेना शुरू कर दिया है। यहां तक कि राजनीतिक दलों द्वारा इस दावे के बावजूद कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जाएंगे जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, अथवा जो आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, यह तर्क दिया जाता है कि 'जीतने की योग्यता' प्रमुख मानदंड है। बिना किसी अपवाद के यह बात सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में सच है।

उम्मीदवारों द्वारा दाख़िल शपथ पत्रों की समीक्षा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उनमें से कुछ हत्याएं तथा डकैतियों जैसे जघन्य आपराधिक मामलों में मुकद्दमे झेल रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले दांवे संभवत: सच हो सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं या आरोप इतने गंभीर नहीं है। कुछ मामलों में प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का परिणाम भी आपराधिक आरोप तय करने के रूप में निकल सकता है। यद्यपि गंभीर अथवा जघन्य आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता।

चुनावों पर नज़र रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (ए.डी.आर.) द्वारा की गई व्यापक समीक्षा में हाल ही में यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे लगभग 25 प्रतिशत उम्मीदवार आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। राज्य के चुनावों में अभी तक पहले तीन चरणों के लिए शपथ पत्र दाख़िल किए गए हैं लेकिन एक चौथाई उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का रुझान लगभग तीनों चरणों में एक जैसा है। विधानसभा चुनावों के लिए जा रहे 4 अन्य राज्य भी बेहतर स्थिति में नहीं हे। ए.डी.आर. तथा पंजाब इलेक्शन वॉच के अनुसार पंजाब में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग 3 गुणा बढ़ गई है जिसमें शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने सबसे अधिक संख्या में ऐसे नामांकितों को मैदान में उतारा है। दोनों संगठनों ने मैदान में कुल 1304 उम्मीदवारों में से 1276 के शपथ पत्रों की समीक्षा करने के बाद यह रिपोर्ट सामने आई।

ए.डी.आर. के ट्रस्टी जसकीरत द्वारा पंजाब इलेक्शन वॉच के परविंद्र सिंह किटना तथा हरप्रीत सिंह के साथ जारी की गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की संख्या इस बार उछल कर 25 प्रतिशत पर पहुच गई है जो 2017 के चुनावों में 09 प्रतिशत थी। ऐसी पृष्ठभूमि वाले 315 उम्मीदवारों में से 65 शिअद, 58 'आप' 16 कांग्रेस, 27 'भाजपा', 04 शिअद (संयुक्त) तथा तीन-तीन बसपा तथा पंजाब लोक कांग्रेस (पी.एल.सी.) से सबंधित है।

कम से कम 15 उम्मीदवारों ने महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है जिनमें दो दुष्कर्म के शामिल हैं। चार उम्मीदवारों पर हत्या से संबंधित मामले हैं जबकि 33 के ख़िलाफ़ हत्या के आरोप मामले है। राज्य के लगभग आधे निर्वाचन क्षेत्र 'रेड अलर्ट' श्रेणी में है। ये वे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां 3 या अधिक उम्मीदवार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुनाव मैदान में उतारने का बढ़ता रुझान चिंताजनक है। यह न केवल राज्यों के मामलों में सच है, यही रुझान संसद में देखा गया है।

ऐसासिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार कुल 363 सांसद तथा विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं तथा सज़ा मिलने के मामले में जन प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत वे अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।

इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्द्र व राज्यों में 39 मंत्रियों ने आपराधिक मामलों की घोषणा की है जो अयोग्यता के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 में शामिल हैं। ऐसासिएशन तथा नैशनल इलेक्शन वॉच ने 2019 से 2021 के बीच 542 लोकसभा सदस्यों तथा 1953 विधायकों के शपथ पत्रों की समीक्षा की थी। 2,495 तथा विधायकों में से 363 (15 प्रतिशत) ने घोषित किया है कि उनके ख़िलाफ़ अदालतों ने क़ानून के अंतर्गत सूचनाबद्ध अपराधों के सिलसिले में आरोप तय किए हैं। इनमें 2096 विधायक तथा 67 सांसद हैं।

पार्टियों में, भाजपा में ऐसे सांसदों अथवा विधायकों की संख्या 83 के साथ सर्वाधिक है, जिसके बाद कांग्रेस के 47 तथा टी.एम.सी. के 25 है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा के 24 पदासीन सदस्यों के ख़िलाफ़ 10 या अधिक सालों से कुल 43 आपराधिक मामले तथा 111 पदासीन विधायकों के ख़िलाफ़ कुल 315 आपराधिक मामले लम्बित हैं।

दुर्भाग्य से विभिन्न संस्थाएं इस बुराई पर नियंत्रण पाने में असफल रही हैं। सर्वोच्च अदालत ने अपराधीकरण के ख़िलाफ़ अपनी नाखुशी ज़ाहिर की है लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हाल ही में इसने इस तथ्य के लिए अफसोस जताया कि विधायिका ने राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए कार्य नहीं किया है। यहां तक कि भारत का चुनाव आयोग भी कोई ज़िम्मेदारी लेने से बच रहा है। ऐसी स्थिति के लिए ख़ुद राजनीतिक दलों को दोष दिया जाना चाहिए। संभवत: केवल मतदाता ही ऐसे नेताओं को ख़ारिज करके एक कड़ा संकेत दे सकते हैं।❑❑

गूगल के भीतर जाति-आधारित भेदभाव के आरोपों के बाद उठा तूफान

गूगल में जातिगत भेदभाव की खबरें आने के बाद दुनियाभर की कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने अमेरिकी टेक कंपनी के सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई को एक खुला पत्र लिखा है।पिछले हसप्ताह अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी थी, जिसमें बताया गया था कि दलित कार्यकर्ता और इक्विटी लैब्स नामक संगठन की संस्थापक थेनमोजी सुंदरराजन का गूगल में होने वाला कार्यक्रम इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि कंपनी के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया। थेनमोजी सुंदरराजन दलित अधिकारों के लिए काम करने वाली एक जानीमानी कार्यकर्ता हैं जो अमेरिका में रहती हैं और लंबे समय से जातिगत भेदभाव के खिलानफ काम कर रही हैं। अप्रैल में 'दलित हिस्ट्री मंथ' के दौरान सुंदरराजन को गूगल न्यूज़ के कर्मचारियों को दलित अधिकारों और उनके साथ होनेवाले शोषण के बारे में जागरूक करने के लिए बुलाया गया था। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है, लेकिन, गूगल के कर्मचारियों ने कंपनी के उच्चाधिकारियों को ईमेल लिखने शुरू कर दिए जिनमें सुंदरराजन को हिंदू-विरोधी और हिंदुओं से नफरत करने वाला बताया गया। इस बारे में बहुत से कर्मचारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर वाशिंगटन पोस्ट से बातचीत में बताया कि गूगल के इंटरानेट और मेलिंग लिस्ट में हज़ारों कर्मचारियों ने सुंदरराजन के विरोध में संदेश लिखे। अखबार लिखता है, कि सुंदरराजन ने सीधे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से अपील की जो एक ऊंची जाति वाले परिवार से आते हैं। उन्होंने पिचाई से अनुरोध किया कि उनके कार्यक्रम को होने दिया जाए लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद सुंदरराजन को कार्यक्रम में आमंत्रित करने वाली गूगल न्यूज में वरिष्ठ अधिकारी तनुजा गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। सात पेज लंबे अपने इस्तीफे में तनुजा गुप्ता ने लिखा है, जानबूझ कर जाति आधारित शोषण को नजरअंदाज करने, विविधता-समानता-समावेश की नीति पर दोहरे मानदंड अपनाने, गोपनीयता को हथियार बनाकर जवाबदेही से बचने और जो बोलते हैं उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई को सामान्य बनाने के कारण गूगल में अब मेरा करियर खत्म होता है। एक हिंदू-जैन परिवार में टेक्सस में जन्मी तनुजा गुप्ता ने अपने इस्तीफे में सिलसिलेवार ब्यौरा देकर बताया है कि किस तरह गूगल ने सुंदरराजन का कार्यक्रम रद्द किया और दलित अधिकारों की अनदेखी की। गुप्ता लिखती हैं, असली पीड़ित थेनमोजी सुंदरराजन हैं जिनकी आवाज को दबा दिया गया, वे लोग हैं जो हर रोज जातिगत भेदभाव झेलते हैं लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनका वीजा न छिन जाए या फिर उनके साथ हेट क्राइम हो सकता है।

ख़ास ख़बरें

चीन और कंबोडिया ने नौसैन्य बंदरगाह विस्तार परियोजना की शुरुआत की

नोम पेन्ह : चीन और कंबोडिया के अधिकारियों ने विवादास्पद नौसैन्य बंदरगाह विस्तार परियोजना की शुरूआत की है तथा अमरीका की इन चिंताओं को ख़ारिज किया कि थाईलैंड की खाड़ी में इस बंदरगाह का इस्तेमाल चीन नौसैन्य ठिकाने के तौर पर कर सकता है। कंबोडिया के रक्षा मंत्री और चीन के राजदूत और अन्य अधिकारियों ने 'रीम नेवल बेस' की आधिकारिक आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया।

जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से की मुलाक़ात

नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अने समकक्ष हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने के उद्देय से भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर भारत में थे। उनकी भारत यात्रा ऐसे समय में हुई जब भाजपा के दो पदाधिकारियों की पैग़ंबर मोहम्मद साहब पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पश्चिमी एशियाई देशों में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है।

भारत वियतनाम ने रक्षा संबंधों के विस्तार कि लिए समझौता

भारत और वियतनाम ने 2030 तक रक्षा संबंधों के दायरे को और व्यापक बनाने के लिए एक विजय दस्तावेज़ और दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के वास्ते 'लॉजिस्टिक सपोर्ट' (समान और सेवाओं की आवाजाही को साझा समर्थन देना) समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के अपने समकक्ष जनरल फान वान गियांग के साथ मुलाक़ात की और दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनने के बाद इन दोनों ने हस्ताक्षर किए।

144 सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान पहुंचे

लाहौर : सिखों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर वार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारत से कुल 144 सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। ईटीपीबी के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने बताया कि 'द इवैक्यूई टस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) और पाकिस्तान गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों ने वाघा सीमा पर तीर्थयात्रियों को आगवान की। उन्होंने बताया कि 144 सिख तीर्थयात्री जोर मेले के सिलेसिले में आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए यहां आएं हैं।

मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में पूरे शौक-ज़ोक से आगे बढ़ना चाहिए

देश के मुसलमानों की हालत ज़ार किसी से छिपी नहीं हैं। मुसलमान भी अपनी इस ख़राब स्थिति से वाक़िफ़ हैं लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसके बावजूद सरकारों ने मुसलमानों के हालात बेहतर बनाने की इस दर्जे कोशिश नही की जितनी करनी चाहिये थी और न ही मुसलमान इस सिलसिले में कोशिश करते नज़र आते हैं। देखा जाये तो मुसलमानों में नफसा नफ्सी का आलम है यानि जिसके दिल में जो आ रहा है कर रहा है। अलबत्ता कुछ लोग अपवाद हैं ज़ाहिर सी बात है कि जब ज़वाल पजीर कौम अपनी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश नहीं करेगी तो इसके सामूहिक परिणाम सामने नहीं आ सकेंगे। यही वजह है कि हमें मुसलमानों में कुछ लोग या परिवार ऐसे नज़र आते हैं जो बहुत अमीर भी हैं और शिक्षित भी लेकिन इनकी आर्थिक और शैक्षिक प्रगति सिर्फ उन तक ही सीमित है और इसके प्रभाव मिल्लत के दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इन सबकी बुनियादी वजह सिर्फ यह है कि उन्होंने अपनी मआशी और तालीमी हालत को बेहतर बनाने के लिये व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश की है उनके सामने कोई ऐसा ख़ाका नहीं था कि वे आम मुसलमानों को भी शिक्षा व आर्थिक मैदान में आगे बढ़ाये इस वक्त पूरी मिल्लत की बहबूदगी की सख़्त ज़रूरत है। यह अलग बात है कि पूरी मिल्लत को ज़वाल की पसतियों से निकाल कर तरक्क़ी की ऊंचाईयों तक ले जाना आसान और पलक झपकते ही हो जाने वाला काम है। इसके लिये सख़्त कोशिश की ज़रूरत है सामूहिक कोशिशों से पूरी मिल्लत को फायदा होगा।

अगर मुसलमानों की सामूहिक तरक्क़ी की बात की जाये तो इसके लिये ज़िन्दगी के विभिन्न विभागों में काम करने की ज़रूरत है। इनमें शिक्षा का विभाग सबसे अहम है क्योंकि शिक्षा एक रोशनी है जो ज़िंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है अगर शिक्षा नहीं तो आर्थिक मैदान में जीत हासिल करना बहुत कठिन है और न ही सामाजिक ज़िन्दगी को अच्छा बताया जा सकता है शिक्षा के बिना दूसरी समस्याओं को भी हल करना कठिन है। आज वही क़ौमें प्रगति कर रही हैं। जो शिक्षित हैं जो शिक्षा में पीछे हैं वे प्रगति में भी पीछे हैं मिसाल के तौर पर हम अरब देशों पर नज़र डाल सकते हैं जिनको अल्लाह ने बहुत से खनिज संसाधनों से मालामाल किया है। मगर इसके बावजूद वे अपने संसाधनों से बहुत कम फायदा उठा रहे हैं जबकि इनके संसाधनों से दूसरे लोग देश जो शिक्षा और तकनीक के मैदान में आगे हैं बहुत फायदा उठा रहे हैं। इससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि शिक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता। इसलिये भारतीय मुसलमानों को शिक्षा प्राप्त करने की ओर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिये। मुसलमानों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस वक़्त बच्चों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। अगर आज उन्होंने यह मोर्चा जीत लिया तो अगले दशकों तक पूरी मिल्लत को इसका फायदा पहुंच जायेगा और अगले कुछ दशकों में वे देश के अहम पदों पर आसीन नज़र आयेंगे और सियासत के मैदान में भी वह इतने पीछे न रहेंगे जितने आज हैं।

गत कुछ दशकों के दौरान देश के मुसलमानों को जिन हालात से गुज़रना पड़ा है और शिक्षा के बिना ज़िन्दगी के मैदानों में दूसरे वर्गों के मुक़ाबले वह जितने पीछे हुये हैं इनसे मुसलमानों में इतनी बेदारी आ गई है कि वे शिक्षा की अहमियत को समझ गये हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की फिक्र करने लगे हैं और इस बात को चाहने लगे हैं कि इनके बच्चों की शिक्षा के लिये अधिक से अधिक संस्थायें, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोली जाय। देश के मुसलमानों के शिक्षा के प्रति इस जज़्बे को अगर दूसरे स्थानों पर भी मिल्लत के नेता कोई रुख देने में सफलता हासिल कर लें तो यक़ीनन अगले कुछ दशकों में ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। मुसलमानों के नेताओं को चाहिये कि वे शिक्षा के लिये संगठित कोशिश करें। संस्थाओं व यूनिवर्सिटीयों के क़याम के लिये आगे आयें। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि तमाम मुस्लिम बच्चों का शिक्षा प्राप्त करना आज के हालात में आसान बात नहीं है क्योंकि आज शिक्षा काफी महंगी हो चुकी है और मुसलमान परिवार अपनी ग़रीबी के कारण इस स्थिति में नहीं हैं कि मोटी रक़में ख़र्च करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा दिला सकें। ऐसे में इनके लिये कोई न कोई राह इस वक़्त निकल सकती है जबकि मुशतरका व मुत्तहदा कोशिशें अमल में लाई जायें।

मुसलमानों के पिछड़ापन को देखते हुये सरकारों को भी मुसलमानों के प्रति नरम रवैया पैदा करते हुये इन के लिये शिक्षा के दरवाज़े खोलने की पूरी कोशिश करनी चाहिये। चिन्ता की बात यह है कि कुछ पार्टियां और सरकारें मुसलमानों की शिक्षा को इसलिये नज़रअंदाज़ करती हैं कि वह इसको सिर्फ मुसलमानों का मसअला समझती रहीं जबकि पूरे देश की समस्या है क्योंकि मुसलमान हिन्दुस्तान का हिस्सा हैं और हिन्दुस्तान को तरक्कीयाफ्ता बनाने के लिये सारे वर्गों को तरक़्क़ीयाफ्ता बनाना ज़रूरी है। 20 करोड़ की आबादी वाले वर्ग को नज़रअंदाज़ करके देश को तरक़्क़ीयाफ्ता बनाने का सपना साकार नहीं हो सकता। लोकतंत्र का तक़ाज़ा है कि देश के सभी बच्चों को शिक्षा हासिल करने के समान अवसर प्राप्त हों और इसी अंदाज़ पर बिना धर्म व मिल्लत का भेदभाव किये तमाम सरकारों को काम करना चाहिये। शैक्षिक और आर्थिक असमानता से देश राष्ट्रीय ऐतबार से खुशहाल व विकसित नहीं हो सकता। □□

नबी पाक का अहतराम

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तमाम मुसलमानों की नज़र में रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम से ज़्यादा कोई महबूब नहीं था लेकिन इसके बावजूद यानि इस क़दर मुहब्बत के बावजूद जब मुसलमान हुजूरे अकरम सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम को देखते तो ताज़ीम के लिए खड़े न होते। उन्हें मालूम था कि हुजूरे पाक सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम इस तरह ताज़ीम के लिए खड़े होने को पसंद नहीं फरमाते यह तरीक़ा अज़म वालों का था।

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल बक़रह क़्र नं॰ 02)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

फिर हमने इस पर भी तुमको माफ कर दिया ताकि तुम अहसान मानो

मतलब यह है कि इस खुले शिर्क के होने पर भी हमने तुमको क्षमा कर दिया और तुम्हारी तौबा स्वीकार की और तुमको तुरंत नहीं मारा ताकि तुम हमारे कृतज्ञ बनो और अहसान मानों।

और हम हमने हज़रत मूसा अलै॰ को किताब और सत्य को असत्य से अलग करने वाले आदेश दिये ताकि तुम सीधे रास्ते पर चलते रहो।

किताब से तात्पर्य तौरेत है और 'सत्य से असत्य को अलग करने वाले आदेश' से तात्पर्य या तो वे आदर्श हैं जिनसे उचित और अनुचित ज्ञात हो या इससे तात्पर्य ह॰ मूसा अलै॰ के चमत्कार हैं जिनसे झूठे सच्चे और इंकारी व मोमिन (ईमानवाले) के बीच का अंतर प्रत्यक्ष हो जाता था या तौरेत है क्योंकि उससे भी सच और झूठ का अन्तर प्रत्यक्ष हो जाता है।

और जब ह॰ मूसा ने अपनी क़ौम से कहा।

क़ौम से तात्पर्य विशेषत: वे लोग हैं, जिन्होंने बछड़े को सज्दा किया।

ऐ मेरी क़ौम तुमने यह बछड़ा बनाकर अपना नुकसान किया है, सो अब अपने पैदा करने वाले से तौबा करो और अपनी-अपनी जान मार डालो।

अर्थात् जिन्होंने बछड़े को सज्दा नहीं किया था वे सज्दा करने वालों को क़त्ल करें। कुछ विद्वानों ने कहा है कि बनी इसराईल में तीन वर्ग बन गये थे एक वे लोग जिन्होंने बछड़े को नहीं पूजा और दूसरों को भी रोका, दूसरे वे लोग जिन्होंने बछड़े की पूजा की, तीसरे वे लोग जिन्होंने स्वयं तो पूजा नहीं की मगर दूसरों को रोका भी नहीं। दूसरे वर्ग को आदेश हुआ कि तुम क़त्ल हो जाओ, तीसरे वर्ग को आदेश हुआ कि तुम क़त्ल करो ताकि मना न करने का जो पाप हुआ उससे माफी मिल जाये और पहला वर्ग किसी भी काम में सम्मिलित नहीं हुआ इसलिए उसको तौबा की आवश्यकता ही न थी।

यह तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के यहां अच्छा है, फिर अल्लाह तुम्हारे हाल पर आकृष्ट हुआ।

विद्वानों का इसमें मतभेद है कि उनका क़त्ल हो जाना ही तौबा था या तौबा की पूर्णता थी, जैसाकि इस्लाम धर्म में जानबूझकर क़त्ल करने वाले की तौबा क़बूल होने के लिए यह भी आवश्यक है कि अपने आपको मृतक के उत्तराधिकारी के हवाले कर दे। उनको अधिकार है कि चाहे बदला लें या माफ़ कर दें।

नि:संदेह वही माफ़ करने वाला बड़ा दयालु है और जब तुमने कहा ऐ मूसा हम आपका कदापि यक़ीन नहीं करेंगे, यहां तक कि हम अल्लाह को खुल्लम खुल्लाह ने देख लें, फिर तुम पर बिजली आ पड़ी और तुम देख रहे थे फिर हमने तुमको मरे पीछे जीवित कर उठाया ताकि तुम अहसान मानों।

उस समय को भी अवश्य याद करो कि इतने अहसान होने पर भी जब तुमने कहा था कि ऐ मूसा हम कदापि तुम्हारा विश्वास न करेंगे कि यह अल्लाह का कलाम है। जब तक आंखों से प्रत्यक्ष रूप में अल्लाह को न देख लें। उस पर बिजली ने तुमको मार डाला।

उसके पश्चात् हज़रत मूसा की दुआ से हमने तुमको फिर जीवित किया। यह घटना इस प्रकार है कि ह. मूसा अलै॰ सत्तर आदमियों को चुनकर तूर पर्वत पर अल्लाह का कलाम सुनने के लिए ले गये। जब उन्होंने अल्लाह का कलाम सुना तो कहा ऐ मूसा पर्दे में कलाम सुनने का हम विश्वास नहीं रखते। अल्लाह को आंखों से दिखाओ। उस पर उन सत्तर आदमियों को बिजली ने मार डाला।

और हमने तुम पर बादल का साया किया और 'मन्न' और 'सलवा' तुम्हारे ऊपर उतारा।

जब फिरऔन डूब चुका और बनी इसराईल अल्लाह की आज्ञा के अनुसार मिस्त्र से शाम देश की ओर चले तो जंगल में उनके तंबू फट गये। सूरज की गर्मी हुई तो उससे बचाव के लिए तमाम दिपन बादल रहता, अनाज न रहा तो मन्न और सलवा खाने को उतारा। मन्न धनिये के दाने के समान एक मीठी वस्तु थी जो रात को ओस के साथ गिरती थी फिर उनके चारों ओर ढेर लग जाते थे प्रात:काल प्रत्येक अपनी आवश्यकता के अनुसार उठा लाता। सलवा एक पक्षी है जिसको बटेर कहते हैं। संध्या के समय उनके चारों ओर हज़ारों की संख्या में इकट्ठी हो जाती, लोग अंधेरा होने पर उनको पकड़ लाते और कबाब बना कर खाते थे लम्बे समय तक यही खाते रहे।

चुनावी जीत के लिए मुफ्तखोरी की होड़

पिछले दिनों कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि देश के कई राज्यों का कर्ज़ बेहद ऊंची स्तर पर पहुंच गया है। उनका कहना था कि समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि उस पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत हैं। सब्सिडी और नक़दी हस्तांतरण के बोझ से सरकारों के खज़ाने कराहने लगे हैं यह सिलसिला यदि यूं ही चलता रहा तो फिर कोई उपाय भी कारगर नहीं रह जाएगा। इस तरह की राजनीति में कोई भी दल और कोई भी राज्य किसी से पीछे नहीं है। आख़िर इस रुझान के पीछे क्या वजह है? असल में पिछले कुछ सालों के दौरान भारत के राजनीतिक-आर्थिक ढांचे में कल्याणकारी लोकलुभावनवाद की एक नई लहर चली है। यह कोई केन्द्र में हो या फिर राज्यों के स्तर पर उनके बीच एक होड़ सी दिख रही है। वे कर्ज़ माफ़ी से लेकर गैस सिलेंडर देने और नक़दी हस्तांतरण पर ज़ोर दे रहे हैं। इस कारण स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी हो रही है। कुल मिलाकर, तमाम सरकारें अपनी कमाई से ज़्यादा ख़र्च करने में लगी है। यह भी सच है कि कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। जैसे कि केन्द्र सरकार की खाद्य सब्सिडी। कोविड महामारी के काल में इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध हुई। फिर भी एक प्रश्न अवश्य उठता है कि भारत में जहां सरकारी खज़ाना पहले से ही दबाव में है वहां खुले हाथ से ख़र्च जारी रखना कितना तार्किक होगा। वह भी तब जब यह राजस्व जुटाने के अतिरिक्त उपाय तलाशने के बिना ही किया जा रहा हो।

ख़र्च के रुझान में इस बदलाव के पीछे स्वाभाविक रूप से चुनावी नैया पार लगाने वाला पहलू है। भारत में चुनाव एक तरह से प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद का अखाड़ा बन चुके है, जिसमें नेता किसी भी कीमत पर जीत का दांव लगाने की जुगत भिड़ाते हैं। व्यापक रूप से यही माना जाता है कि मतदाता ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का अहसान किसी पार्टी के पक्ष में मतदान से चुकाते हैं। इतने बड़े स्तर पर इन योजनाओं में होने वाले खर्च के कारण यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत जुलाई, 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडू सरकार एवं अन्य मामले में चुनाव आयोग को तलब कर चुकी है। मुफ्तखोरी से जुड़े मामले में बीते दिनों फिर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस आशय की एक याचिका लगाई थी। उनकी अर्ज़ी चुनाव आयोग को संबोधित है कि क्या आयोग ऐसी नियमावली बना सकता है जो राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा पत्र में किए जाने वालों वायदों को लेकर अनुशासित बना सके। अपने जवाब में आयोग ने उचित ही कहा कि किसी कानूनी अधिकार के अभाव में वह इस मामले में कुछ ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं है, ऐसी नीतियां आर्थिक रूप से अव्यवहारिक और सरकारी खज़ाने की सेहत के लिए खतरनाक है। इसका निर्णय तो मतदाताओं को ही करना होगा।

जहां राजनीतिक दल इस प्रकार की लोकलुभावनवादी होड़ में लगे हुए हैं तो यह पड़ताल भी ज़रूरी है कि ऐसी नीतियां आख़िर मतदाताओं को कितना प्रभावित करती है? इसमें

भले ही तथ्य यह साबित करें कि सरकारी खज़ाने से खैरात बांटने का चुनावी संभावनाओं पर बहुत सीमित असर होता हो, लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला हाल फिलहाल थमा नहीं दिखता। नेता बड़ी दुविधा में हैं। वे जानते हैं कि ऐसी लुभावनी पेशकश उन्हें बढ़िया गवर्नेंस रिकॉर्ड के अभाव में चुनाव के दौरान शायद कुछ राजनीतिक बढ़त दिलाने में सहायक हो सकती है।

कोई संदेह नहीं कि ये नीतियां चुनावी लाभ का सबब ज़रूर बनती है, लेकिन इनके प्रभाव को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। यदि इस प्रकार का लोकलुभावनवाद ही चुनाव जीत में निर्णायक रहे तो सत्तारूढ़ दल और उसके प्रत्याशियों को बहुत कम बार हार का सामना करना पड़ता दिखाई देगा। जबकि भारत का रुझान यही दिखाता है कि यहां चुनाव जीतकर पुनः सत्ता में आना काफी कठिन माना जाता है। ऐसी पेशकश का चुनावी प्रभाव जानने के लिए दलों को यह जानना होगा कि किन लाभार्थियों ने उनके पक्ष में मतदान किया और किन्होंने नहीं। भारत में यह पता करना मुश्किल है क्योंकि यह चुनाव आयोग मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। लोकनीति सीएसडीसी द्वारा 2009 में संकलित डाटा के अनुसार नेताओं के लिए विशेषकर यह पता करना कठिन है कि स्थानीय चुनावों में मतदाताओं ने किसे वोट दिया था। इस बहस में सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि पार्टियां मतदाताओं को मुफ्तखोरी वाली नीतियों के संभावित नुकसान की जानकारी दिए बिना ही उनकी पेशकश करती है। इसका कारण यही है कि यदि किसी को कुछ मुफ्त पेशकश की जाए तो यही आसार अधिक है कि वह उसे अस्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि पार्टियां इन नीतियों की वकालत करती है, क्योंकि उनके अपने सर्वेक्षण इन योजनाओं की लोकप्रियता को दर्शाते हैं। जब मतदाताओं को यह पता चले कि इन चुनावी रेवड़ियों के चलते सरकारी धन के उन पर ख़र्च होने के कारण उन्हें किन अन्य लाभा से वंचित होना पड़ सकता है तब संभव है कि वे मुफ्तखोरी की इन योजनाओं को ख़ारिज कर दें।

क्या भारतीय राजनीति इसी राह पर चलती रहेगी? अर्थव्यवस्था अभी दबाव में है। केन्द्र राज्यों को मिलाकर जीडीपी के अनुपात में कर राजस्व 18 प्रतिशत है तो व्यय अनुपात 29 प्रतिशत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने हाल में चेताया कि यदि राज्यों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी का चलन बंद नहीं किया तो देश को आर्थिक मोर्चे पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह राजकोषीय आपदा को आमंत्रण दे सकता है।

भले ही तथ्य यह साबित करें कि सरकारी खज़ाने से खैरात बांटने का चुनावी संभावनाओं पर बहुत सीमित असर होता हो, लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला हाल फिलहाल थमा नहीं दिखता। नेता बड़ी दुविध ा में हैं। वे जानते हैं कि ऐसी लुभावनी पेशकश उन्हें बढ़िया गवर्नेंस रिकॉर्ड के अभाव में चुनाव के दौरान शायद कुछ राजनीतिक बढ़त दिलाने में सहायक हो सकती है। वे इससे भी अवगत हैं कि गुप्त मतदान और अन्य दलों द्वारा भी यही दांव चलने से गेंद पूरी तरह मतदाताओं के पाले में रहती है। यह भी सच है कि कोई नेता इस तरह तरह की लोकलुभावन योजनाओं से पूरी तरह मुंह फेरने का जोखिम नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में राजनीतिक दल और मतदाता इस सहमति पर पहुंचें कि ऐसी योजनाओं की मांग और आपूर्ति केवल नुकसान ही करती है।□□

बिहार: क्या बिहार तरह अन्य राज्य भी कुछ क़दम उठाएंगे?

जैसा कि पिछले दिनों संभावना थी बिहार में हुई सर्वदलीय बैठक में जातिवार जनगणना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके बाद अब इसे कैबिनेट की मंज़ूरी मिलना एक औपचारिकता भर ही कहा जाएगा। यानि तय हो गया कि केन्द्र सरकार के स्पष्ट रुख़ के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भले जातिवार जनगणना होना मुमकिन न रह गया हो, बिहार सरकार अपने तई राज्य में यह गिनती करवाएगी। चाहे तकनीकी अड़चनों से बचने के लिए इसे औपचरिक तौर पर जनगणना न कह कर जातिवार गणना कहा जाए या इसी तरह का कोई और नाम दे दिया जाए, माला यही है कि जब केन्द्र सरकार ने कास्ट सेंसस की राह रोकी तो बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इसके लिए एक नई राह निकाल ली।

पर प्रश्न है कि क्या यह राह बिहार तक ही सीमित रहेगी? ऐसा लगता नहीं है। महाराष्ट्र में भी विधान सभा पिछले वर्ष जातिवार जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। तमिलनाडू की सरकार भी केन्द्र से जातिवार जनगणना करवाने की मांग कर चुकी है। अब जब बिहार इस राह पर आगे बढ़ चुका है तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अन्य राज्य सरकारें भी इस दिशा में पहल करेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो सर्वदलीय बैठक के बाद बाक़ायदा यह उम्मीद ज़ाहिर कर चुके हैं कि एक बार पूरा देश कवर हो जाएगा। अगर कुछ राज्यों में भी ऐसा हुआ तो देश में किस तरह के हालात बनेंगे।

क्या जैसा कि केन्द्र सरकार और सत्तारुढ़ भाजपा के कई नेता कहते रहे हैं, इन राज्यों में जातिवार जनगणना से विभाजनकारी प्रवृत्तियां जोर पकड़ेंगी? और क्या इन राज्यों में भाजपा का रुख़ बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा बिहार में रहा? क्या जनगणना से जुड़े आंकड़ों में राज्यवार अंतर आगे चलकर कई और जटिलताओं को जन्म नहीं देंगे? क्या भाजपा शासित राज्यों में भी सरकारें केन्द्र के रुख़ से अलग जातिवार जनगणना के पक्ष में फैसला करेंगी? कुल मिलाकर, बिहार की इस पहल ने ढेरों प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इन्हीं में एक बड़ा सवाल यह भी है कि केन्द्र में सत्तारुढ़ कोई राष्ट्रीय पार्टी इतने महत्वपूर्ण मसले पर ऐसा ढीला ढाला रुख़ कैसे अपना सकती है कि 'जातिवार जनगणना देश और समाज के हित में हैं या नहीं, इस सीधे सादे सवाल का भी पार्टी की सभी इकाइयां कोई एक स्पष्ट जवाब न दे सकें? वोट बैंक की राजनीति से जुड़ी विवशताओं का ही एक रूप शायद यह भी है। बहरहाल, बिहार की इस पहल ने साफ कर दिया है कि जातिवार जनगणना का यह प्रश्न केन्द्र सरकार के स्पष्ट फैसले के बावजूद निपटा नही है। तमाम दलों और सरकारों को आगे इस बहस से निपटने की तैयारी जारी रखनी होगी ताकि दुविधा, संदेह और उलझन की स्थितियां भविष्य में उनसे गलत फैसले न करवा ले।□□

खेल तथा युवा सेवाएं विभाग के बजट के लिए ज़रूरी सुझाव

इकबाल सिंह संधू

किसी भी विभाग या कार्यालय को सही ढंग से चलाने के लिए ज़रूरी है कि वह अपने वार्षिक बजट पर बहुत अधिक ध्यान दें तथा बारीकी से इसकी तैयारी करें लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि कार्यालय तथा विभाग सबसे कम ध्यान अपने वार्षिक बजट पर देते हैं। यह भी आमतौर पर देखा गया है कि जब तक सरकार द्वारा वार्षिक बजट तैयार करे भेजने के लिए काफी नोटिस, याद पत्र नहीं आ जाते तब तक हम अपना वार्षिक बजट तैयार करने का काम शुरू नहीं करते।

भगवंत मान सरकार ने अपने वार्षिक बजट, जिसे उन्होंने 'जनता' नाम दिया है, पर जनता से जुझाव मांगने का निर्णय लिया। जो कि एक अत्यंत अच्छा प्रयोग है क्योंकि कार्यालयों में बैठे बाबू तथा अधिकारी के मुकाबले फील्ड में लोगों तथा योजनाओं के लाभार्थियों को अधिक पता होता है कि बजट में किन किन कार्यों तथा योजनाओं के लिए अधिक राशि की ज़रूरत है।

वर्तमान समय में सरकारों के लिए [illegible] मौजूदा हालातों में खेलें तथा युवा सेवाएं [illegible] पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इस विभाग को वित्तीय वर्ष 2022 में केवल 147 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया था जिससे खिलाड़ियों की ज़रूरतें तो क्यों पूरी होनी थीं केवल विभाग के वेतन तथा दफ्तरी खर्चे ही मुश्किल से चल सके थे। इसलिए यदि पंजाब की जवानी को बचाना है तो युवाओं को नशे से हटाकर खेल मैदानों में लाने के लिए खेलों के बजट में वृद्धि करके इसे 1000 करोड़ रूपए का किया जाना ज़रूरी है।

हरियाणा खेल विभाग ने राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप, अकादमियों तथा खेल कोचिंग कैम्पों के लिए खिलाड़ियों का रोज़ाना खुराक़ राशि/भत्ता प्रति खिलाड़ी 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया है जबकि पंजाब में यह केवल 200 रूपए ही है।

मौजूदा समय में विभिन्न खेल संघों के लिए अपने सिर पर पंजाब के अगल अलग आयु वर्गों में 6 टीमें (पुरुष तथा महिला) नेशनल चैम्पियनशिप में भेज सकना मुश्किल हो गया है क्योंकि रेल किराए में पहले जो 50 प्रतिशत की छूट मिलती थी वह अब रेलवे ने वापस ले ली है तथा इसी प्रकार टीमों के 15 दिनों के कोचिंग कैम्प पर जो आज प्रति खिलाड़ी रहन सहन का कम से कम 400 रुपए का खर्चा आता है, यह पहले खेल विभाग करता था, अब खेल संघों के लिए अपने स्तर पर करना मुश्किल है।

पंजाब में ज़िला ओलम्पिक एसोसिएशनों को पुनजीर्वित किया जाए तथा हर खेल के ब्लॉक/जिला तथा राज्य स्तर के मुकाबले ज़िला/ राज्य स्तर की खेल एसोसिएशनों के साथ मिलकर पंजाब खेल विभाग द्वारा हर वर्ष करवाए जाने सुनिश्चित बनाए जाएं। इन ज़िला ओलिम्पिक एसोसिएशनों को ज़िला स्तरीय मुक़ाबलों के लिए 05 लाख रुपए की वार्षिक ग्रांट जारी करने का बजट में प्रावधान किया जाए।

पंजाब सरकार ने पंजाब से आलोप हो रही रही महिला हॉकी का पुनर्जीवित करने के लिए जालंधर में ओलिम्पियन सुरजीत सिंह हॉकी अकादमी की तर्ज़ पर महिला हॉकी अकादमी जालंधर

बाक़ी पेज 11 पर

सिर्फ विश्व कप में हो टी-20 क्रिकेट : रवि शास्त्री

पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री मानते हैं कि टी-20 प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज के लिए नहीं है, बल्कि इसे सिर्फ विश्व कप तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। शास्त्री की यह टिप्पणी भारत की दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ पांच मैचों की टी-20 सीरीज से पहले आई है। भारत के सबसे सफल कोचों में से एक शास्त्री को यह भी लगता है कि खेल प्रेमियों के उत्साह को देखते हुए जहां तक छोटे प्रारूप की बात है तो सबसे अच्छा तरीक़ा फ्रेंचाइजी क्रिकेट के साथ दो वर्ष में टी-20 विश्व कप होगा। शास्त्री ने कहा, 'टी-20 में काफी द्विपक्षीय क्रिकेट हो रहा है। मैंने यह पहले भी कहा है, यहां तक कि जब मैं भारतीय टीम का कोच था, तब भी। यह मेरे सामने हो रहा था। यह टी-20 क्रिकेट फुटबॉल की तरह से होना चाहिए जहां आप सिर्फ विश्व कप खेलते हो। द्विपक्षीय टूर्नामेंट को कोई याद नहीं रखता।' भारतीय कोच के तौर पर शास्त्री का कार्यकाल पिछले वर्ष ख़त्म हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय कोच के तौर पर पिछले छह साल के कार्यकाल के दौरान विश्व कप को छोड़कर एक भी टी-20 मैच याद नहीं हैं उन्होंने कहा, 'एक टीम विश्व कप जीतती है, वे इसे याद रखती है। दुर्भाग्य से हम नहीं, इसलिए मुझे यह भी याद नहीं। दुनियाभर में फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेला जा रहा है, प्रत्येक देश को अपना फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने की अनुमति है, जो उनका घरेलू क्रिकेट है और फिर प्रत्येक दो वर्ष में आप एक (टी-20) विश्व कप खेलो।'

स्वास्थ्य

ज़्यादा देर तक बैठे रहने से स्वस्थ शरीर पर बुरा असर

इंसान का शरीर एक गतिशील प्राणी के हिसाब से बना है, न कि घंटों एक ही जगह पर टिके रहने के हिसाब से, इसलिए अगर नौकरी के कारण 8-10 घंटे बैठे रहने की मजबूरी हो तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसे आसनों को अपनाना चाहिए, जिससे हम लंबे समय तक बैठे रहकर भी स्वस्थ रह सकें। ऐसे में आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी 10 क़दम चलने का भी मौक़ा मिले तो ब्रिस्क वॉक करें यानि तेज-तेज़ क़दमों से चलें। पूरे दिन में ऐसे टुकड़े ज़रूरी निकाल लें कि पूरे एक घंटे की यह चाल फेर हो जाये। करीब 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लगभग 8 घंटे बैठे रहने से शरीर को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए इंसान को 60 से 75 मिनट तक ब्रिस्क वॉक या मध्यम तीव्रता वाले एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि दिनभर बैठकर बिताने वाले लोग अगर इतनी देर भी व्यायाम नहीं करते हैं तो यह उनके लिए उतना ही ख़तरनाक है, जितना मोटापा या सिगरेट पीने से होता है।

एक और ध्यान देने वाली बात है कि टेलीविजन के सामने घंटों जो बैठे रहते हैं, वो भी एक किस्म से अपने आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर ऑफिस के 8 घंटे के बाद बचे हुए 4-5 घंटे आप टीवी के सामने स्थिर पड़े रहकर बिताते हैं तो इसके बाद आप अगर एक घंटे की एक्सरसाइज करते हैं तो भी यह कम है।

दिन का इतना लंबा समय बैठ कर बिताने से हृदय, धमनियां, हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। यह डायबिटीज, कैंसर और दिल की बीमारियों को आमंत्रित करने जैसा है। एक्टिव रहने से दिमाग़ तेज़ होता है, दिल, मांसपेशियां और हड्डियां मज़बूत होती हैं। दफ्तर में लंच के समय एक छोटी वॉक के लिए जा सकते हैं, सुबह या शाम को दौड़ने या साइकिल चलाने की आदत डाल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन हर दिन 30 मिनट व्यायाम की सलाह देता है, जो कि उन लोगों के लिए ही सही है, जो दिन में ज़्यादा समय एक्टिव रहते हैं। आमतौर पर जो दिन के ज़्यादातर समय बैठे रहे हैं, उनके लिए यह व्यायाम का समय पर्याप्त नहीं है। शायद यही वजह है कि यूरोप के कई देशों में मसलन डेनमार्क, नार्वे और स्विटजरलैंड में ज़्यादातर लोग ऑफिस पैदल या फिर साइकिल से जाते हैं, जिस कारण उनकी पर्याप्त एक्सरसाइज हो जाती है लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में इसका चलन नहीं है। खासकार भारत में! हमारे यहां एक प्रतिशत दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी अपने दफ्तर साइकिल से नहीं पहुंचते। इस कारण हमारे यहां यह समस्या बढ़ती जा रही है। वास्तव में हमारे जैसे देश में लोग जी-जान लगाकर पढ़ते इसलिए हैं कि अच्छी साहबों वाली नौकरी मिल जाये, जिसमें दिनभर कुर्सी में बैठे रहना पड़ता हो, लेकिन ऐसी सोच अपनी सेहत के साथ बुरा मज़ाक करने जैसा है। ऐसी जॉब, हमसे, हमारी सेहत और ज़िन्दगी छीन रही है। पीठ और गर्दन में दर्द में इन दिनों लोगों अक्सर दर्द रहता है, इसका कारण दिनभर एक ही मुद्रा में बैठे कम्प्यूटर में काम करना है। ख़ासकर अगर आप काम करते-करते कम्प्यूटर स्क्रीन में इस कदर घुस जाते हैं कि आपकी पीठ सीधी रहने की जगह मुड़ी रहती है तो इसका मतलब यह कि आपको आप से कोई लगाव नहीं है। दिन भर अक्सर एक ही तरह बैठकर काम करते रहने से दिल संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और शरीर में खून ठीक तरह से पंप नहीं हो पाता। नतीजतन कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। डायबिटीज को भी आप इसके ज़रिये आमंत्रित कर रहे होते हैं। वास्तव में आप जितनी देर तक बैठे रहेंगे पैन्क्रियाज उतना ही ज़्यादा इंसुलिन बनाता रहेगा और क्योंकि आपका शरीर बैठे-बैठे कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा तो वो और भी ज़्यादा इंसुलिन बनाएंगे, इसका नतीजा होगा डायबिटीज। सिर्फ डायबिटीज ही नहीं साथ में मोटापा भी बढ़ेगा। फिर चाहे आप भले चाय, काफी या शुगर फ्री की गोलियां ही क्यों न मिलाते हों। कोक की जगह भले डायट कोक पीएं, तले हुए चिप्स की जगह भले ही लॉ फेट बिस्किट खाएं लेकिन अगर दिन में ज़्यादातर समय एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं तो वज़न बढ़ना तय है। दिनभर बैठकर काम करने से दिमाग़ भी मोटा हो जाता है। जो काम एक घंटे में हो सकता है, उसके लिए आप धीरे-धीरे डेढ़ और फिर दो घंटे से ज़्यादा का समय लेने लगेंगे। दिनभर बैठे रहने से हम एक तरह से कैंसर को भी आमंत्रित कर रहे होते हैं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी दिनभर बैठने की वजह से हो सकती है।□□

अतीत की मनमानी व्याख्या

राम पुनियानी

आरएसएस की 100 से अधिक अनुषांगिक संस्थाएं हैं और इस सूची में नित नए नाम जुड़ते जा रहे हैं। संघ की अनुषांगिक संस्थाओं में से जो प्रसिद्ध हैं उनमें बीजेपी, वीएचपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल शामिल हैं। परंतु इनके अतिरिक्त भी संघ से जुड़े दर्जनों ऐसे संगठन और संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम बहुत नहीं जानते परंतु जो देश के अलग-अलग हिस्सों में उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। जब बीजेपी शासक दल नहीं थी तब भी आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं उतनी ही सक्रिय थीं। 1980 के बाद से देश में आरएसएस की गतिविधियों में तेजी से इजाफा हुआ है और पिछले आठ सालों से तो ये संस्थाएं दिन-रात काम कर रही हैं। इन सभी संस्थाओं के लिए आरएसएस के मुखिया के वचन वेद वाक्य हैं जिनका पालन वे हर हाल में करते हैं।

मोहन भागवत के हालिया (3 जून 2022) बयान को इसी संदर्भ में देख जाना चाहिए। भागवत ने कहा कि संघ काशी और मथुरा में मस्जिदों के स्थान पर मंदिरों का निर्माण करने की मांग को लेकर कोई आंदोलन नहीं चलाएगा। उन्होंने कहा कि वे अदालतों के निर्णय को स्वीकार करेंगे। जो लोग समाज में शांति और सद्भाव चाहते हैं उन्हें संघ प्रमुख का यह बयान चिंता हरने वाला लगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, ज्ञानवापी मुद्दे के उठने के बाद से देश भर में सैकड़ों मस्जिदों के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वे मंदिरों के मलबे पर बनी हैं। जो संस्थाएं और व्यक्ति इस तरह के दावे कर रहे हैं वे कहीं न कहीं संघ परिवार से जुड़े हुए हैं।

इसका एक उदाहरण कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा हैं जिन्होंने कहा है कि मंदिरों को तोड़कर 36,000 मस्जिदें बनाई गई हैं और इन तोड़े गए मंदिरों पर पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। ईश्वरप्पा इस तरह की सोच और समझ रखने वाले नेताओं का एक नमूना भर हैं। शायद बीजेपी के प्रमुख नेताओं और आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में पता नहीं है। यह अधिनियम देश में स्थित सभी उपासना स्थलों के रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है और कहता है कि ऐसे सभी स्थलों का स्वरूप वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। इसके अतिरिक्त, एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जे) से संबंधित कानून भी है। जिन मस्जिदों की बात की जा रही है वे सैकड़ों साल पुरानी हैं। जाहिर है कि संघ परिवार के लोगों को यह पता तो होगा ही कि जब तक वर्तमान कानून लागू हैं तब तक कानूनी रूप से किसी उपासना स्थल के स्वरूप और चरित्र को नहीं बदला जा सकता।

भागवत का दावा है कि यह केवल आस्था का मामला है। हिन्दुओं का मुसलमानों से कोई बैर नहीं है। केवल उन स्थानों पर दावे किए जा रहे हैं जिनमें हिन्दुओं की विशेष श्रद्धा है।'' इस बयान में बहुत दम नहीं है। हिन्दुओं के सैकड़ों उपासना स्थल हैं जिनमें केदारनाथ, हरिद्वार, द्वारिका, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम आदि शामिल हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी हम लोगों को तीर्थयात्रा पर ले गए थे। मुझे याद है कि उस समय हम लोग हरिद्वार और प्रयागराज गए थे और मेरे दादाजी ने वायदा किया था कि अगली बार वे हमें कुरूक्षेत्र ले जाएंगे।

अयोध्या, काशी और मथुरा भी पवित्र स्थल हैं परंतु उन्हें उनकी पवित्रता के लिए नहीं वरन् इसलिए चुना गया है क्योंकि उनका इस्तेमाल विवाद खड़ा करने के लिए किया जा सकता है। यह सोचना गलत होगा कि भागवत या आरएसएस अपनी नीति या लक्ष्य बदल रहे हैं। आरएसएस की विचारधारा कई दशकों से वही है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाओ और भारत के 'स्वर्णिम अतीत' का महिमामंडन करो। भागवत ने यह भी कहा है कि हमें हजारों मस्जिदों में शिवलिंग ढूढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या यह कहकर वे इस आरोप की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम राजाओं ने देश में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा है? रिचर्ड ईटन जैसे अध्येता हमें बताते हैं कि मुस्लिम शासकों द्वारा जमींदोज किए गए मंदिरों की संख्या बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताई जा रही है। उनके अनुसार हिन्दू शासकों ने भी हिन्दू मंदिर तोड़े हैं।

आरएसएस के मुखिया के बयान से इस धारणा की पुष्टि होती है कि भारत में इस्लाम का प्रसार हमलावरों ने किया। यह ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। हम जानते हैं कि इस्लाम, भारत में अरब व्यापारियों के जरिए आया और कई लोगों ने जातिगत दमन से बचने के लिए हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने दो पत्रों (खेतरी के पंडित शंकरलाल को 20 सितंबर, 1892 और बिटठलदास देसाम्र को नवंबर 1894 में लिखे गए) में धर्मपरिवर्तन के कारणों की व्याख्या करते हुए लिखा ''धर्मपरिवर्तन ईसाईयों और मुसलमानों के अत्याचारों के कारण नहीं हुए। वे ऊँची जातियों के अत्याचारों के कारण हुए।''

भागवत के अनुसार, मुसलमानों के हमलों में सैकड़ों देवस्थानों को इसलिए ध्वस्त किया गया ताकि स्वतंत्रता हासिल करने की इच्छा रखने वालों के मनोबल को कुचला जा सके। हिन्दू समाज उन पर बहुत जोर देता है। भागवत की मूल सोच यही है और यही सोच एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाते हुए अंततः नफरत में बदल जाती है, जिसका वमन नुपूर शर्मा ने टीवी पर और नवीन जिंदल ने सोशल मीडिया पर किया। यह सचमुच शर्मनाक है कि भाजपा ने इन दोनों के खिलाफ तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जब तक कि खाड़ी के देशों ने हमारे राजदूतों को बुलाकर लताड़ नहीं लगाई। कुछ लोगों का मानना है कि भागवत ने जो कुछ कहा है वह संघ की सोच में बदलाव का संकेत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संघ प्रमुख के इस बयान से 'अनुशासित' आरएसएस कार्यकर्ताओं की मंदिर-मस्जिद विवादों से संबंधित गतिविधियों पर कम से कम अस्थायी रूप से ब्रेक लगेगा। इसके अतिरिक्त नफरत की राजनीति के चलते देश में कुछ नए तत्व उभर आए हैं जो आरएसएस के नियंत्रण में नहीं हैं परंतु जिन्हें पता है कि सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं करेगी। इसका एक उदाहरण धर्मसंसदों में दिए जा रहे जहर-बुझे भाषण हैं। धर्मसंसदें बिना किसी संकोच या डर के नफरत फैला रही हैं। इसी तरह के तत्वों में से एक है तेजस्वी सूर्या। हाल में आस्ट्रेलिया में आयोजित उनके एक कार्यक्रम को स्थानीय लोगों के विरोध के कारण रद्द करना पड़ा। क्या भविष्य में भी विदेशी दबाव नुपूर शर्मा और तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों को नियंत्रित करेगा? अगर ऐसा होता भी है तब भी यह एक अस्थायी उपाय होगा।

2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में भागवत के तीन भाषणों से कुछ लोगों को लगा था कि आरएसएस की दिशा में मूलभूत परिवर्तन आ गया है। यह कयास एकदम गलत सिद्ध हुए।

अब, जबकि जिन्न बोतल से बाहर आ गया है भागवत यह कोशिश कर रहे हैं कि हालात एक सीमा से ज्यादा न बिगड़ें। परंतु इसके बाद भी संघ की मूलभूत समझ तो यही है कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे मंदिर गिराए और तलवार की नोंक पर लोगों को मुसलमान बनाया।

हिन्दुओं के आराधना स्थलों के ध्वंस की कोई भी तार्किक और तथ्यात्मक विवेचना, दुष्प्रचार की सुनामी के सामने ठहर ही नहीं पाती। हिन्दू समाज की 'आहत भावनाएं' राजनीति के अखाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यह तो गनीमत है कि पुष्यमित्र शुंग और उसके जैसे अन्य राजाओं द्वारा बौद्ध विहारों को नष्ट करने की कहानियां इतिहास के पन्नों में ही कैद हैं वरना विध्वंस विशेषज्ञों को एक नग्र परियोजना मिल जाती।❑❑

शेष.... जातिगत जनगणना....

गरीब है। इसके बाद हाशिए पर छूटे लोगों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

यह बताते चलें कि 1931 में हुई जातिगत जनगणना में बिहार में ब्राह्मण 4.7 प्रतिशत, भूमिहार 2.9 प्रतिशत, राजपूत 4.2, कायस्थ 1.2 और बनिया 0.6 प्रतिशत पाए गए थे। उस समय बनिया को ऊंची जातियों में ही रखा गया था और इनका कुल औसत 13.6 प्रतिशत था। पिछड़ी जातियों में यादव 11 पअतिशत कुर्मी 3.6 प्रतिशत और कोइरी 4.1 प्रतिशत थे। अति पिछड़ी जातियों की कुल आबादी 32 प्रतिशत थी। 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े हालांकि जारी नहीं हुए, लेकिन माना जाता है कि उसमें बिहार में मुसलमानों की आबादी 16.9 प्रतिशत, यादव 14.4 प्रतिशत, कुशवाहा 6.4 प्रतिशत, कुर्मी 4, ब्राह्मण 4, भूमिहार 6, राजपूत 3 और कायस्थों की आबादी एक प्रतिशत पाई गई थी।

अगर ये आंकड़े सही हैं, तो आबादी के जातिगत समीकरण में विगत दशकों में बड़ा बदलाव पहले ही आ चुका है। आबादी का जातिगत समीकरण बदलने का बड़ा कारण पलायन भी हो सकता है। बहरहाल, बिहार के फैसले की चर्चा पूरे देश में है। दिलचस्पी के साथ लोग अन्तिम आंकड़ों का इंतज़ार करेंगे। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए समय सीमा भी तय कर ली है। फरवरी 2023 तक इस काम को अंजाम दे दिया जाएगा। जनगणना से जुड़े जो बाकी सवाल है उनका हल भी सामने आएगा। अगर जाति आधारित जनगणना कराकर इसकी रिपोर्ट जारी करने में बिहार सफल रहा, तो वह 91 वर्ष बाद ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा।❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

उन्मूलन हो जाने के बाद अब उसके टीक का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए संभव है कि इस वायरस के लिए तेजी से फैलना पहले के मुकाबले आसान हो गया हो। इन तमाम आशंकाओं के बीच भी घबराहट की स्थिति न बने इसके लिए यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अभी भी मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले बहुत कम है और इनके आम लोगों के बीच फैलने की गुंजाइश भी कम ही बताई जाती है। लेकिन एक बात तोा यह कि ब्रिटेन में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है यानि ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिनमें संक्रमित व्यक्ति के अफ्रीकी देशों से आने वाले किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में आने की कोई बात नहीं है दूसरे, इस वायरस के बारे में अब भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है इसलिए किसी भी सूरत में सावधानी नहीं छोड़ी जा सकती।❑❑

शेष.... खेल तथा युवा सेवाएं....

में शुरू करने का जो निर्णय किया है उसे अमली जामा पहनाने के लिए खिलाड़ियों के रहन-सहन, खेलों के सामान तथा सालाना खर्चों के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। पंजाब सरकार के खेल विभाग में नीति के अनुसार ओलिम्पियन खिलाड़ियों को 5000 रूपए तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1000 रुपए दी जाने वाली पेंशन बहुत कम है।

उल्लेखनीय है कि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में यह पेंशन काफी समय से 15,000 रुपए दी जा रही है। इस पर पुनर्विचार करते हुए यह पेंशन ओलिम्पियन खिलाड़ियों को कम से कम 20,000 रुपए तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 15 हजार रूपए प्रति माह का बजट में प्रावधान किया जाएगा।

जालंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में लगी पुरानी/खराब फ्लड लाइटें एल.ई.डी. लाइटों से बदलने, वी.आई.पी. ब्लॉक के फिक्स्ड कुर्सियां, साउंड सिस्टम लगाने, स्टेडियम में मल्टीमीडिया सेंटर कम साइड हॉकी ग्राउंड की रिपेयर के साथ साथ खस्ताहाल स्टेडियम की पूर्ण रेनोवेशन के लिए चालू वर्ष बजट में कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए।

पंजाब में हर जिले/डिवीजन में या कलस्टर बनाकर खेल अकादमियां स्थापित की जाएं। उदाहरण के तौर पर फुटबॉलर होशियारपुर, कपूरथला तथा जालंधर में अधिक मकबूल हैं - इसलिए फुटबॉल अकादमी इन्हीं जिलों में कलस्टर बनाकर होशियारपुर या माहिलपुर में स्थापित की जा सकती है। इसी प्रकार हम हॉकी, एथलैक्टिस, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, वालीबॉल आदि खेलों की अकादमियां भी बना सकते हैं।

बजट में गांव/कस्बे/शहर के लिए जिम, खेल किटों को राजनीतिज्ञ हित को मुख्य रखते बांटने की अघोषित पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाई जाए जिससे जहां हर वर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान होता है वहीं खिलाड़ी अपनी ज़रूरत के अनुसार खेलों के सामान से वंचित रह जाते हैं।

जिन स्टेडियमों में ब्लॉक/तहसील/जिला/राज्य/अखिल भारतीय स्तर के खेल मुक़ाबले करवाए जाते हैं उन्हें पुनः रूप से किराया मुक्त किया जाए क्योंकि इनको चलाने वाली संस्थाओं के पास अपनी आय का कोई साधन नहीं होता बल्कि ये लोगों के सहयोग से ऐसी चैम्पियनशिप्स करवाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड समारोह हर साल आयोजित किया जाना चाहिए पर इसके लिए एक तिथि निश्चित की जानी चाहिए। जैसा कि 29 अगस्त जिस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।

पंजाब सरकार के खेल विभाग द्वारा राज्य में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से चार एस्ट्रोटर्फ लगाई जा रही हैं जिनमें से सुरजीत हॉकी स्टेडियम जालंधर में एस्ट्रोटर्फ लग कर तैयार हो चुकी हैं इसके अतिरिक्त लुधियाणा, अमृतसर, बादल, मोहाली वगैरह में पहले ही एस्ट्रोटर्फ लगी हुई है।

हम सभी पंजाबी खिलाड़ी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर से यह पूर्ण आशा करते हैं कि वे उक्त सुझावों पर ग़ौर करते हुए खेलों के विकास के लिए जनता के बजट में से आवश्यक फंड खेलें तथा युवक सेवाएं विभाग पंजाब को उपलब्ध करवाएंगे।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **5 June 2022** Posting Days : **MON-TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

•लापता बच्चे•महंगाई की मार •और अब मंकी पॉक्स

लापता बच्चे

देशभर में गुम हो जाने वाले बच्चों को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। अमूमन हर वर्ष ग़ायब होने हुए बच्चों के आंकड़े सामने आते हैं, इससे संबंधित रिपोर्ट पेश की जाती है, इस समस्या के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा होती है और फिर कुछ समय बाद इस मसले पर एक विचित्र शांति छा जाती है। ऐसा लगता है कि शासन से लेकर समाज तक लापता बच्चों की समस्या को लेकर सहज हो जाता है। जबकि जिस घर से कोई बच्चा गुम हो जाता है, उसमें पसरे दुख का बस अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। ग़ायब हो गए बच्चों को किन त्रासद हालात से गुज़रना पड़ता है, इसकी कल्पना भी किसी भी संवेदनशील इंसान को दहला देगी। इस समस्या को लेकर सरकार और संबंधित महकमों का रुख़ और उनकी कार्यशैली कैसी रही है, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हर अगले वर्ष लापता होने वाले बच्चो के आंकड़ों में इज़ाफ़ा बताता है कि इस त्रासदी के प्रति सरकारों और प्रशासन ने एक तरह से अनदेखी की मुद्रा ग्रहण कर रखी है।

ग़ैर सरकारी संगठन 'क्राई' की 'लापता बच्चों पर स्थिति रिपोर्ट' में एक बार फिर ऐसे बच्चों को लेकर जो आंकड़े और तथ्य सामने आए हैं, वे यह बताने के लिए काफी है कि तमाम चिंताओं के बावजूद यह समस्या विकराल और जटिल होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर भारत के चार प्रमुख राज्यों में बच्चों के लापता होने का मामलों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। 2021 में मध्य प्रदेश में हर रोज़ औसतन 29 और राजस्थान में 14 बच्चे लापता हुए। इसके अलावा, दिल्ली के आठ पुलिस जिलों में इसी वर्ष हर दिन पांच बच्चे पांच बच्चे लापता हो गए। एक त्रासद तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में लापता हुए बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में पांच गुना अधिक है। पूरे देश में कमोबेश यही हालत है। सरकारों की ओर से हर अगले रोज़ यह दावा किया जाता है कि वह क़ानून व्यवस्था में सुधार और आम लोगों की सुरक्षा के मोर्चे पर आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पहले के मुकाबले ज़्यादा शिद्दत से काम कर रही है। लेकिन हक़ीक़त इसके उलट दिखती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में ज़्यादा बच्चे गुम हो गए। प्रश्न यह है कि यह सुधार की किस तस्वीर को रेखांकित करता है। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि लापता हो गए बच्चों को किस त्रासदी का सामना करना पड़ता है। मानव तस्करी के दायरे में कैसी की वीभत्सताएं पलती है और उसमें ग़ायब करके लाए गए बच्चों को किस तरह झोंका जाता है, इसकी सच्चाई भी अक्सर सामने आती रही है। क्राई की रिपोर्ट में ही यह बताया गया है क लड़कों के मुकाबले पांच गुना ज़्यादा लड़कियां लापता हुई हैं। यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि मानव तस्करों के जाल में फंसाई गई बच्चियों को कैसे देह व्यापार की आग में झोंक दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चे भीख मांगने, घरेलू नौकर के रूप में काम करने और अन्य जगहों पर बाल मज़दूरी करने से लेकर दूसरे अमानवीय हालात में फंस जाते हैं उन्हें यौन शोषण के अड्डों या अंगों के कारोबारियों को भी बेच दिया जाता हैं इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों को कई मौक़ों पर फटकारा है और इस समस्या पर क़ाबू पाने के लिए तंत्र बनाने का निर्देश दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारों की प्राथमिकता सूची में यह समस्या कोई महत्व नहीं रखती।

महंगाई की मार

हाल में रिजर्व बैंक ने इशारा दिया है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि वह रैपो रेट बढ़ाने वाला है। हाल में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कुछ रियायत देते हुए ये घोषणा की कि अब महंगाई कम हो जाएगी। इसके बरक्स बढ़ती महंगाई को लेकर चौतरफा हा-हाकार है, मगर इसे रोकने को लेकर सरकार के प्रयास सफल होते नज़र नहीं आ रहे। थोक महंगाई बढ़ कर 15.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। तेल की कीमतों पर क़ाबू पाने के प्रयास बेनतीजा साबित हो रहे हैं। काफी समय तक रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज़ दरों में इसलिए कोई बदलाव नहीं किया, ताकि बाज़ार में पैसे का प्रवाह कुछ बढ़े। मगर ऐसा नहीं हुआ, तो उसे ब्याज़ दरों में परिवर्तन करना पड़ा। उसने रेपो दरों में चालीस आधार अंक की बढ़ोत्तरी कर दी। इससे बैंकों को कर्ज़ वसूली पर जाने वाली दरों में बढ़ोत्तरी का रास्ता खुल गया। कई बैंक अपनी दरों में वृद्धि कर चुके हैं। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी ब्याज़ दर में 0.1 प्रतिशत की और बढ़ोत्तरी कर दी है। उसका मानना है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। रसोई गैस की कीमतें आम उपभोक्ता की पहुंच से दूर हो रही हैं। खुदरा महंगाई भी लगातार बढ़ रही हैं। पांच खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का दम भरने वाली सरकार के सामने अब महंगाई पर क़ाबू पाने का कोई उपाय भी नज़र नहीं आ रहा।

महंगाई का गणित कई चीज़ों पर निर्भर करता है। उसे किसी एक सूत्र को पकड़ कर नहीं साधा जा सकता। इसमें ईंधन की बढ़ती कीमतें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसका सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ता है। ढुलाई महंगी होने से उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उसी के अनुसार उस पर लगने वाले करों में भी वृद्धि हो जाती है। इसी तरह हवाई यात्रा और निजी तथा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करने वालों को दैनिक ख़र्च बढ़ जाता है। मगर सरकार तेल की कीमत को क़ाबू में नहीं कर पा रही हैं पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे वैट में कटौती करें, ताकि उपभोक्ता को कुछ राहत मिल सके। मगर केन्द्र सरकार कई साल से जो तेल पर ऊंचा उत्पादन शुल्क वसूल रही है, उसमें कटौती की बात नहीं की जा रही। इस वक्त पैट्रोल पर करीब 26 रुपए उत्पादन शुल्क वसूला जा रहा है। यह ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी हुई है, जिसका असर हमारे यहां पड़ रहा है। मगर जब महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, तो उत्पादन शुल्क घटाने पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता।

महंगाई की मार लोगों पर इसलिए भी अधिक पड़ रही है कि उनकी कमाई नहीं बढ़ रही। बहुत सारे लोग अपनी रोज़ी रोज़गार नौकरी गंवा चुके हैं। बहुतों ने अपने भविष्य निधि से पैसे निकलवा कर भी गुज़ारा चलाने का प्रयास कर लिया। ऐसे में अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो उनका जीना दूभर हो जाता है। खुद सरकार का दावा है कि वह देश के अस्सी करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन बाट रही है यानि इतने लोगों के हाथ में कोई रोज़गार नहीं है इसलिए सरकार को महंगाई पर क़ाबू पाने के लिए समग्र रूप से विचार करने की ज़रूरत है।

और अब मंकी पॉक्स

पहले महामारी और फिर युद्ध से उपजे मुश्किलात झेलती दुनिया के सामने मंकी पॉक्स के रूप में एक नई चुनौती आ रही है। विभिन्न देशों में इसके सौ से ज़्यादा मामलों की पुष्टि होने के बाद इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। कुछ दिन पहले इसके मामले इतने कम थे कि किसी तरह का ख़तरा नहीं माना जा रहा था। मगर पिछले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन के साथ-साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया और बेल्जियम सहित 12 देशों में इसके मरीज़ पाए गए जाने की पुष्टि की गई है। यही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन ने कहा है कि कुछ दिनों में इसके और भी मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि यह कोई नई बीमारी नहीं है। अफ्रीकी देशों में इसके हजारों मामले हर वर्ष सामने आते हैं। लेकिन यह पहला मौक़ा है जब अफ्रीका से बाहर इतने बड़े इलाके में इसका प्रसार देखा जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण का मतलब है कि यह पिछले कुछ समय से फैल रहा होगा जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। राहत की बात यह है कि अभी तक इन देशों में इस संक्रमण से किसी की मौत होने की ख़बर नहीं है। अफ्रीकी देशों के जिन इलाकों में यह बीमारी आ रही है वहां भी ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। औसतन दस मामलों में सात मौत देखी जाती है। मगर स्कॉल पॉक्स परिवार के इस वायरस का अचानक विभिन्न महादेशों में फैलाव कैसे हो गया यह गुत्थी वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है। इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है लेकिन इस आशंका को ख़ारिज नहीं किया जा सकता कि कहीं इस वायरस ने अपना रूप तो नहीं बदला है। अगर ऐसा हुआ होगा तो नए वेरिएंट के रूप में इसके लक्षण, संक्रमण की क्षमता वगैरह में भी परिवर्तन संभव है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारी इस संभावना का पता लगा रहे हैं कि क्या सेक्स के ज़रिए भी इसका संक्रमण होता है? यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि स्मॉल पॉक्स का

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा **9811198820** पर
SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c **10310541455**
Branch: **Indraprastha Estate**
IFS Code: **SBIN0001187**

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173